लखनऊ

रविवार, 19 अप्रैल, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 235

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

"मन में इच्छा, दिल में हिम्मत और कदमों में निरंतरता ये तीन चीज़ें हर दिन को सफल बना देती हैं।"

TODAY WEATHER

DAY 28° Hi

NIGHT 17° Low

संक्षेप

भारत से इस वर्ष 1.75 लाख से अधिक लोग करेंगे हज, दिल्ली एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट रवाना

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत से 2026 की हज यात्रा शनिवार से शुरू हो रही है, पहला बैच आज सऊदी अरब के मक्का के लिए रवाना हुआ। सुबह से ही पहली उड़ान के लिए यात्री हवाई अड्डे पर पहुंचने लगे थे। इस जत्थे में देश भर के विभिन्न प्रस्थान बिंदुओं से सऊदी अरब के लिए रवाना हो रहा है। इस वर्ष कुल 1,75,025 तीर्थयात्रियों के वार्षिक हज यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां भी एयरपोर्ट पर मौजूद दिखीं। हज व्यवस्थाओं के लिए नोडल निकाय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने भारत की हज समिति, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और सऊदी अधिकारियों के साथ समन्वय में व्यापक तैयारियां की हैं ताकि निर्बाध रसद व्यवस्था और जमीनी स्तर पर बेहतर सुविधा सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने कहा, आज हज 2026 की पहली फ्लाइट है, जिसमें 371 यात्री अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। मैं सभी को दिल से बधाई देना चाहती हूं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी सुविधाओं को लगातार बढ़ाया जा रहा है और हमारी सरकार यह पक्का करने की पूरी कोशिश कर रही है कि उनकी यात्रा जितनी हो सके उतनी आसान, सुखद और सुखद हो। एक तीर्थयात्री ने कहा, अल्लाह की मर्जी से और सबकी दुआओं से, अल्लाह ने मुझे हज 2026 का सौभाग्य प्रदान किया है। आज, अल्लाह की मर्जी से, हमारी पहली उड़ान भारत के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से है। एक तीर्थयात्री ने कहा, हम सभी के लिए दुआ करेंगे। हर मुसलमान को वहां पहुंचने का अवसर मिलना चाहिए। यह मेरे जीवन में पहली बार है कि मुझे ऐसी यात्रा करने का मौका मिला है, और मैं बहुत खुश हूं।

तमिलनाडु में भीषण सड़क हादसा : खाई में गिरी टूरिस्ट वैन, 9 लोगों की मौत; 4 घायल

कोयंबटूर। तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले के वालपराई पहाड़ी क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। केरल से आई एक टूरिस्ट वैन गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि चालक समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
जानकारी के मुताबिक, वैन में कुल 13 लोग सवार थे, जो केरल के मलप्पुरम जिले के निवासी थे। सभी लोग वालपराई घूमने आए थे और वापस लौटते समय यह हादसा हो गया। वैन जब वालपराई-पोलाची पहाड़ी मार्ग से नीचे उतर रही थी, तभी 13वें हेयरपिन मोड़ पर चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद वैन बैरियर से टकराकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस के अनुसार, 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें 7 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। बाद में एक घायल ने पोलाची सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। घटना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

विपक्ष ने ईमानदारी से भरे प्रयास की भ्रूण हत्या की... महिला आरक्षण पर बोले प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए महिला आरक्षण पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संसद में सरकार की ओर से लाया गया बिल एक ईमानदार प्रयास था लेकिन इस कोशिश की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। देश की नारी शक्ति के अपराधी हैं। कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम 8:30 बजे से महिला आरक्षण पर देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 'मेरे लिए देशहित सर्वोपरि है, जब कुछ लोगों के लिए दल हित सबकुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को ही इसका खामियाजा उठाना पड़ता है।' ये देश के संविधान के अपराधी हैं। जिन लोगों ने आधी आबादी का अधिकार छीना, उन्हें इस पाप की सजा मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने एक तरह महिलाओं के सपने को कुचल दिया। आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे नारी शक्ति को उसका हक नहीं दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी। देश की नारी शक्ति देख रही थी। मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थीं। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। पूरे देश ने विपक्ष की इस हरकत को देखा है।

नारी अपमान नहीं भूलती: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कल विपक्ष ने जो भी किया वह सिर्फ टेबल पर थाप नहीं थी। वह नारी के स्वाभिमान पर उसके आत्म सम्मान पर चोट थी। पीएम ने कहा कि नारी वैसे सब भूल सकती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस के उसके सहयोगियों के व्यवहार की कसक, हर नारी के मन में हमेशा रहेगी। देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तो वह याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था, खुशियां मनाईं थीं।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बवाल : 10 हजार महिलाओं का राहुल गांधी के घर मार्च, कांग्रेस पर बरसीं सीएम रेखा

नई दिल्ली, एजेंसी। विपक्षी दलों के विरोध के चलते संसद में शुक्रवार को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के गिरने के बाद शनिवार दोपहर बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के हर कोने से आ कर 10 हजार से अधिक महिलाएं मोती लाल नेहरू मार्ग पर विरोध स्वरूप एकत्र हुईं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा एवं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य वरिष्ठ नेताओं के संबोधन के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सुनहरी बाग स्थित घर की ओर बढ़ीं। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल

गांधी का पुतला फूंक रही महिलाओं को दिल्ली पुलिस ने भारी बल प्रयोग कर रोका और तितर बितर किया और प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा और कमलजीत सहरावत, बांसुरी स्वराज, योगिता सहित प्रमुख महिला नेताओं को गिरफ्तार कर संसद मार्ग थाने ले गई। इस दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि कल देश के संसद सदन में एक ऐतिहासिक निर्णय होने वाला था जिसमें साधारण परिवार से आने वाली माताएं बहनों को अपना हक मिलने वाला था लेकिन विपक्ष के नेता जिन्हें अपने परिवार से बाहर कुछ दिखता नहीं है। उन्होंने ना सिर्फ इस बिल को पास होने से रोका बल्कि देश की आधी आबादी वाली मातृशक्ति के हक को खत्म करने का काम किया है। वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि आज देश भर में मताएं-बहनें सड़कों पर अपने हक के लिए खड़ी है लेकिन विपक्ष इस पर सिर्फ राजनीति कर रहा है। हालांकि विपक्ष इस आक्रोश से वंचित नहीं रह सकता है।

एआई विकल्प नहीं सहयोगी है, इससे डरे नहीं : मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत

बंगलूरू। भारतीय न्यायपालिका में तकनीक का प्रवेश एक बड़े बदलाव का संकेत है, लेकिन यह बदलाव मानवीय संवेदनाओं और संवैधानिक नैतिकता की कीमत पर नहीं होना चाहिए। शनिवार को बंगलूरू में आयोजित न्यायिक अधिकारियों के 22वें द्विवार्षिक राज्य-स्तरीय सम्मेलन में देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और न्याय प्रणाली के अंतर्संबंधों पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी।

'एआई के युग में न्यायपालिका की पुनर्कल्पना' विषय पर बोलते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को एआई से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, 'जब आपके सामने जटिल कानूनी सवाल आते हैं, तो आप अधिक धैर्य और गहराई से विचार करते हैं। एआई के साथ भी हमें यही रुख अपनाना होगा। इसे सावधानी और सचेत होकर इस्तेमाल करें, जिससे आपके भीतर बैठा 'जज' किसी तकनीकी उपकरण से प्रभावित न हो।'

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एआई केवल एक सहायक हो सकता है, विकल्प नहीं। न्याय की प्रक्रिया केवल डाटा का विश्लेषण नहीं है, बल्कि यह एक चिंतनशील और नैतिक कार्य है जो संवैधानिक मूल्यों से निर्देशित होता है।

एआई की 'भ्रम' वाली दुनिया से खतरा

मुख्य न्यायाधीश ने एआई के बढ़ते खतरों, विशेषकर हैलुसिनेशन यानी भ्रम पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि एआई का दुरुपयोग भ्रामक याचिकाओं और सतही तौर पर आकर्षक लेकिन कानूनी रूप से खोखले दावों को पेश करने के लिए किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि इससे पहले से ही बोझ तले दबी न्याय व्यवस्था पर दबाव और बढ़ेगा।

परिसीमन पर राहुल गांधी का हमला, बोले– संसद में तमिलनाडु की आवाज दबाना चाहती है भाजपा

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि परिसीमन से संबंधित हालिया संसदीय कदम का उद्देश्य संसद में तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व को कम करना है। आगामी चुनावों से पहले राज्य में अपना प्रचार अभियान तेज करते हुए उन्होंने यह बात कही। तिरुवल्लूर जिले के पोन्नेरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गांधी ने इस कदम को दक्षिणी राज्यों को प्रभावित करने वाली एक व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बताया। क्षेत्रीय चिंताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और भाजपा राज्य की पहचान को निशाना बना रहे हैं।

राहुल ने कहा कि स्वाभाविक रूप से, वर्षों से मेरा तमिलनाडु के लोगों के

साथ एक रिश्ता बन गया है। मेरा जन्म तमिलनाडु में नहीं हुआ है, और मेरा परिवार भी तमिलनाडु से नहीं है, फिर भी मैं खुद को तमिलनाडु का ही मानता हूँ। आरएसएस और भाजपा तमिलनाडु, तमिल भाषा और तमिल संस्कृति पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई तमिलनाडु की तमिल भाषा और संस्कृति पर हमला करने की।

संसद में हुए घटनाक्रम पर गांधी ने दावा किया कि इस विधेयक के पीछे एक गुप्त उद्देश्य छिपा है। उन्होंने कहा कि कल संसद में उन्होंने एक नया विधेयक पेश किया। उन्होंने इसे महिला विधेयक बताया, लेकिन वह तो 2023 में ही पारित हो चुका था। उस विधेयक के पीछे छिपा एजेंडा परिसीमन था। इसका मकसद भारत की संसद में तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व को कम करना और दक्षिणी तथा छोटे राज्यों को कमजोर करना था। हमने कल संसद में उस विधेयक को हरा दिया।

अपनी व्यापक राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि भारत "राज्यों का संघ" है, जहाँ प्रत्येक राज्य को समान स्थान मिलना चाहिए। संघ में प्रत्येक राज्य की आवाज़ होनी चाहिए और उसे अपनी भाषा बोलने और अपनी परंपरा की रक्षा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। भाजपा के शासन के तरीके की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री एक राष्ट्र, एक नेता, एक भाषा, एक जनता की बात करते हैं, तो वे भारत के संविधान पर हमला कर रहे होते हैं।

57 सीटों पर कांटे की टक्कर : क्या भाजपा मारेगी बाजी या टीएमसी करेगी 'खेला'

नई दिल्ली, एजेंसी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में सियासी लड़ाई इस बार सिर्फ बड़े चेहरों, रैलियों और नारों तक सीमित नहीं है। असली मुकाबला उन सीटों पर सिमटता दिख रहा है, जहां पिछली बार जीत-हार का अंतर बेहद कम रहा था। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं— इस बार जीत और हार के पीछे कई कारण होंगे, लेकिन एक बड़ा कारण उन सीटों का गणित भी होगा, जहां कुछ हजार या कुछ सौ वोटों ने नतीजे तय किए थे। दरअसल, 2021 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े इस बार की रणनीति की रीढ़ बन चुके हैं। राज्य की 294 सीटों में बहुमत के लिए 148 सीटें जरूरी हैं, लेकिन करीब 57 सीटें ऐसी हैं जहां जीत-हार का अंतर 8000 वोट से कम रहा था। इनमें से कई सीटों पर मुकाबला इतना करीबी था कि नतीजे कुछ सौ वोटों में तय हुए। यही सीटें इस बार सत्ता की असली चाबी

बन सकती हैं। बड़ी जीत, लेकिन भीतर छिपी कड़ी टक्कर 2021 के चुनाव में टीएमसी ने 213 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था, जबकि भाजपा 77 सीटों पर सिमट गई थी। अन्य दलों को 4 सीटें मिली थीं। ऊपरी तौर पर यह एकतरफा जनादेश दिखता है, लेकिन गहराई से देखने पर तस्वीर अलग है। कई सीटों पर मुकाबला बेहद कांटे का रहा, जिसने यह संकेत दिया कि वोटर का 57 सीटों का माइक्रो गणितः जहां हर वोट निर्णायक इन 57 सीटों पर मुकाबले की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिनहाटा सीट पर जीत का अंतर महज 57 वोट था।

दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, राष्ट्रीय राजधानी को दहलाने की तैयारी में जुटे 4 युवक गिरफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चार ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये युवक देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें दबोज लिया। इन चारों आरोपियों को अलग-अलग राज्यों महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से IED बनाने का सामान और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी जांच जारी है।

पुलिस के मुताबिक ये सभी युवक कट्टरपंथी सोच से प्रभावित थे और नफरत करने के मकसद से काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये लोग गजवा-ए-हिंद जैसे खतरनाक विचारों को बढ़ावा दे रहे थे और इसके लिए दूसरों को भी उकसा रहे थे, ताकि

अपने नापाक मंसूबों को पूरा कर सकें।

सोशल मीडिया ग्रुप्स में जुड़े हुए थे

जांच में सामने आया है कि ये आरोपी सोशल मीडिया के गुप्त (क्लोज्ड) ग्रुप्स में जुड़े हुए थे, जहां आतंकी विचारधारा, जिहाद और हथियारों की बात होती थी। जांच में पता चला कि इन ग्रुप्स के जरिए ये लोग नए लोगों को जोड़ने और उन्हें भड़काने का काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक इनमें से दो आरोपी मिलकर एक रिमोट कंट्रोल IED (बम) बनाने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए जरूरी सामान जैसे बॉल बेयरिंग, कील, खिलौना कार आदि जुटाए जा चुके थे। जांच में यह भी पता चला कि एक आरोपी ने दिसंबर 2025 में दिल्ली आकर लाल किला और इंडिया गेट जैसी महत्वपूर्ण जगहों की रेकी (जांच) की थी। उसने सोशल मीडिया पर लाल किले की फोटो के साथ आपत्तिजनक पोस्ट भी शेयर की थी, ताकि लोगों को भड़काया जा सके। गिरफ्तार युवकों में से एक सोशल मीडिया के जरिए पैसे (क्राउड फंडिंग) जुटा रहा था, जबकि दूसरा हथियार चलाने और ट्रेनिंग दिलाने का वादा कर रहा था। इसके लिए लोगों से पैसे भी मांगे जा रहे थे। चारों आरोपी साधारण परिवारों से आते हैं और ज्यादातर 10वीं तक पढ़े हुए हैं। जांच में पता चला कि इनमें से कोई मैकेनिक है, कोई सिक्योरिटी गार्ड, तो कोई प्लंबर का काम करता है।

केंद्र सरकार पर उदयनिधि ने लगाए गंभीर आरोप ; अपने गृह क्षेत्र से छठी बार चुनाव लड़ेंगे पलानीस्वामी

नई दिल्ली, एजेंसी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल को है। इसी दौरान उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही एआईएडीएमके के महासचिव पलानीस्वामी एडप्पाडी विधानसभा क्षेत्र से छठी बार चुनाव लड़ रहे हैं।

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने शनिवार को केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य को धनराशि जारी नहीं करती है। इसके साथ ही तमिलनाडु के अधिकारों को छीनने का आरोप लगाया। पश्चिमी इरोड जिले के गोबिचेट्टीपलयम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, डीएमके युवा विंग के प्रमुख ने दावा किया कि केंद्र ने शिक्षा के लिए 3,000 करोड़ रुपये की धनराशि जारी नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया, 'केंद्र सरकार ने हमारे सभी अधिकार छीन लिए हैं।' केंद्र सरकार के परिसीमन प्रस्ताव के संबंध में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन देश में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने केंद्र सरकार के इस कदम के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने दावा किया कि यह भारत गठबंधन के लिए एक बड़ी जीत थी, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष द्वारा इसके खिलाफ मतदान करने के बाद बहुमत के अभाव में विधेयक पराजित हो गया। वहीं, इस बार के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी छठी बार एडप्पाडी विधानसभा यानी की अपने गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं।

'महिलाओं का मसीहा बनना आसान नहीं': प्रियंका गांधी बोलीं- लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की रची जा रही थी साजिश

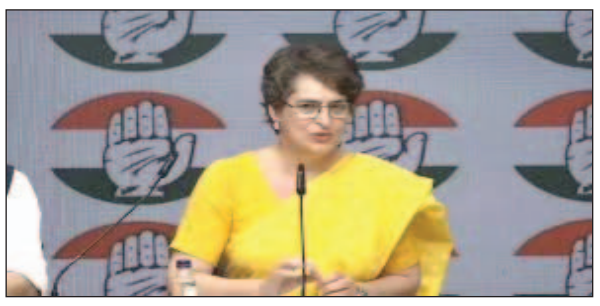

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पारित न होने के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ, वह लोकतंत्र और संविधान की बड़ी जीत है।

प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार संघीय ढांचे को कमजोर करने और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रही थी, जिसे विपक्ष ने मिलकर विफल कर दिया। उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ संविधान और देश की जीत है, बल्कि विपक्ष की एकजुटता की भी जीत है, जो सत्ताधारी दल के नेताओं के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी।

महिलाओं के मुद्दे का इस्तेमाल सत्ता में बने रहने के लिए किया जा रहा है

उन्होंने आगे कहा कि सरकार किसी भी तरह सत्ता में बने रहने की रणनीति बना रही है और इसके लिए महिलाओं के मुद्दे का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। उनके मुताबिक, सरकार की सोच थी कि अगर बिल पास हो जाता तो उसे राजनीतिक फायदा मिलता, और अगर नहीं होता तो वह अन्य दलों को महिला विरोधी बताकर खुद को महिलाओं का मसीहा दिखाने की कोशिश करती। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं का मसीहा बनना आसान नहीं है और सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने इसे एक राजनीतिक रणनीति करार दिया।

प्रियंका ने दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरा

केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के हालिया फैसलों में अंतरराष्ट्रीय दबाव साफ दिखता है। अमेरिका के साथ हुए समझौते का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी शर्तें सामान्य परिस्थितियों में कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करता। महंगाई को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि गैस, फल-सब्जियों और रोजमर्रा की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का सबसे ज्यादा बोझ महिलाओं पर पड़ रहा है। उनके मुताबिक, सरकार इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए राजनीतिक गतिविधियों और प्रचार का सहारा ले रही है।

कांग्रेस सांसदों ने कहा कि आपकी मंशा अच्छी थी, लेकिन राहुल मानते ही नहीं : रिजिजू

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा में बीते दिन संविधान संशोधन से जुड़े विधेयक पारित नहीं हुए। इसे लेकर एक तरफ कांग्रेस जश्न मना रही है और उसकी तरफ से केंद्र सरकार पर कई आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं इसके जवाब में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजनीति से प्रेरित होकर और महिलाओं को अधिकार न देने की मानसिकता के साथ कांग्रेस और विपक्ष ने संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं होने दिया। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि इससे देश की महिलाओं को नुकसान हुआ है। देश की बागडोर संभालने और निर्णय प्रक्रिया में उन्हें प्रतिनिधित्व देने का प्रयास सफल नहीं हो सका। अब कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कल संसद में जो हुआ उसे देश ने देखा है। नारी शक्ति बिल, बहुमत न मिलने के कारण पारित नहीं हो सका है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने इस गंभीर मुद्दे को भी राजनीति से देखा और राजनीति से प्रेरित होकर काम किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के साथ न आने के कारण नारी शक्ति बिल को दो तिहाई बहुमत हमें नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जिस तरह का काम किया है उसका जवाब अब उन्हें महिलाओं को देना होगा। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को उनका हक दिला रहे थे लेकिन विपक्ष महिलाओं को आरक्षण न देकर इसका जश्न मना रहा है।

'मेरे से अब जिया नहीं जाएगा...', साथियों को भेजा ये वॉयस मैसेज, 10वीं में 92% आने पर भी छात्रा ने दी जान

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। कानपुर में लक्ष्य से तीन फीसदी कम नंबर आने पर एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले छात्रा ने अपने कुछ साथियों को एक वॉयस रिकार्डिंग भी भेजी थी। दरअसल, 92 फीसदी अंक कम नहीं होते पर वैशाली सिंह को 95 फीसदी अंक की चाहत थी। चाहत अधूरी रह गई तो उसने गुरुवार शाम फंदे से लटककर जान दे दी।

पनकी रतनपुर शिवालिक भवन निवासी छात्रा वैशाली सिंह बुधवार को सीबीएसई 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद से मायूस थी। फंदा लगाने से पहले छात्रा ने अपने कुछ साथियों को मोबाइल पर वॉयस रिकॉर्डिंग भेजी थी। इसमें उसने जीने की इच्छा खत्म होने व उस पर खर्च

किए जाने वाले रुपये बर्बाद होने की आशंका का जिक्र किया था। पुलिस ने जांच के लिए छात्रा का मोबाइल फोन जब्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वैशाली अर्मापुर स्थित केंद्रीय विद्यालय में सीबीएसई बोर्ड से 10वीं की छात्रा थी। परिवार में मां काजल, 19 वर्षीय भाई प्रिंस है।

प्राइवेट कर्मी पिता वीरेंद्र सिंह की दो साल पहले मौत हो चुकी है। काजल पीरोड स्थित एक मॉल में काम करती हैं। प्रिंस कुछ साल पहले पढ़ाई छोड़ चुका है। काजल ने बताया कि गुरुवार को वह मॉल गई थीं। दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक बेटी को कई कॉल की लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। उन्होंने प्रिंस को कमरे में भेजा तो वह वैशाली का शव फंदे पर लटका देख चीख पड़ा। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पनकी इंस्पेक्टर मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि तनाव के कारण छात्रा के खुदकुशी की बात सामने आई है। मोबाइल कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गई हूं...

खुदकुशी से पहले छात्रा ने अपने कुछ साथियों को एक वॉयस रिकार्डिंग भेजी थी। इसमें छात्रा कह रही थी कि मेरे से अब जिया नहीं जाएगा... मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गई हूं... अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। मुझे बहुत डर लगता है... मां मुझ पर इतना पैसा खर्च कर रही हैं... कहीं उनका पैसा बर्बाद न हो जाए।

मां ने लगाया आरोप

मृतका की मां काजल ने आरोप लगाया कि बेटी पर स्कूल वाले पढ़ाई का काफी दबाव डाल रहे थे। इस कारण वह रात-रात भर पढ़ती रहती थी। इसी के तनाव में उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली।

भाई बोला... टीचर्स मुझसे तुलना कर बहन को करते थे परेशान

छात्रा के भाई प्रिंस का कहना था कि वह भी केंद्रीय विद्यालय में 11वीं का छात्र रहा है। शरारती होने के कारण उसके नंबर अच्छे नहीं आते थे। 11 अक्तूबर 2024 को पिता के देहांत के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। प्रिंस ने आरोप लगाया कि उसके पढ़ाई छोड़ने के बाद स्कूल के कुछ टीचर उसकी बहन की तुलना उससे करते हुए पढ़ाई के लिए दबाव बनाते थे।

प्रिंस के अनुसार, बहन अक्सर उसे बताती थी कि टीचर उससे कहते थे कि तुम प्रिंस की बहन हो, तुम्हारे अच्छे अंक नहीं आ पाएंगे। इस कारण वह परेशान होकर तनाव में रहने लगी थी। भाई के अनुसार, वैशाली ने कहा था कि जिन टीचरों ने उससे स्कूल में गलत बोला, वह उनको साबित करके दिखाएगी। पढ़ाई से उसने 92 प्रतिशत अंक भी पाए। वह लोग खुशी मना ही नहीं पाए थे कि बहन ने इतना बड़ा कदम उठा लिया।

माता-पिता बच्चों से करें बात उम्मीदों का दबाव न बनाएं

आजकल बच्चों से उम्मीदें ज्यादा रखी जाती हैं। जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो बच्चों को लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई। ऐसे में माता-पिता बच्चों पर उम्मीदों का दबाव न बनाएं। बच्चा मन की बात करे, ऐसा वातावरण बनाकर रखें। इस उम्र में बच्चों का ब्रेन विकसित होता है और नकारात्मकता तेजी से उन पर हावी होती जाती है। उन्हें बताएं कि अंक ही सब कुछ नहीं होते हैं। सचिन तेंदुलकर अगर दसवीं में अंकों के पीछे भागते तो आज उन पर पूरा देश गर्व नहीं करता।-डॉ. धनंजय चौधरी, विभागाध्यक्ष, मानसिक रोग, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज

बीडीएस छात्रा ने हॉस्टल में फंदा लगा दी जान

वहीं, एक और दूसरी घटना कानपुर में ही सामने आई है। कानपुर के कल्याणपुर में गूबा गार्डेन स्थित एक हॉस्टल में रह रही बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) की छात्रा नाजिया हसन (23) ने बुधवार रात फंदा लगाकर जान दे दी। वह मूलरूप से बिहार के जिला मुंगेर की रहने वाली थी। शुक्रवार सुबह पिता बिहार से कानपुर पहुंचे। रुंधे गले से बोले... उन्होंने तो बेटी के क्लीनिक के लिए जमीन भी खरीद ली थी लेकिन बेटी ने इस तरह सबको धोखा दे दिया। कल्याणपुर पुलिस के अनुसार, छात्रा नाजिया हसन मंधना स्थित महाराणा प्रताप डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बीडीएस थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रही थी। अगले साल उसका सेमेस्टर पूरा होना था। छात्रा के पिता ब्लॉक से सेवानिवृत्त क्लर्क हैं। पुलिस के अनुसार, पिता से छात्रा की मंगलवार को ही फोन पर बात हुई थी। उसने कोई तनाव नहीं बताया था। परिजन उसके खुदकुशी करने का कारण पुलिस को नहीं बता सके। सुसाइड नोट भी नहीं मिला।

भव्य रूप में मनाया जाएगा भगवान परशुराम जन्मोत्सव

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जनपद में पिछले 26 वर्षों से निरंतर चल रही भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाने की परंपरा इस वर्ष और भी व्यापक रूप लेने जा रही है। जहां इसकी शुरुआत मात्र तीन लोगों द्वारा की गई थी, वहीं इस बार जिले भर में डेढ़ सौ से अधिक स्थानों पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा।

जागृति ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में शहर के एक होटल के सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम के चित्र पर दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण के साथ हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर डी.एस. मिश्रा ने भगवान परशुराम के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संयोजक पंडित रुपेश शुक्ल ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए हर विप्र परिवार से अपने घर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाने की अपील की। कार्यक्रम में परशुराम युवा वाहिनी मिशन परशुराम चौक के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित तिवारी ने भी संबोधित करते हुए सभी से रविवार को परशुराम चौक पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी जगदंबा प्रसाद गोस्वामी, प्रदेश अध्यक्ष विनोद मिश्रा, रमेश शर्मा, राम कीरत मिश्रा, सभासद गिरीश मिश्रा, अखिलेश मिश्रा सहित कई गणमान्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में पूर्व सभासद राजदेव शुक्ल, पत्रकार श्री प्रकाश पांडेय समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। इस बार का आयोजन न केवल परंपरा का विस्तार है, बल्कि सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक चेतना का भी प्रतीक बनकर उभर रहा है।

फर्जी अस्पतालों पर शिकंजा, रजा हॉस्पिटल की जांच शुरू

सुल्तानपुर। नगर क्षेत्र में संचालित रजा हॉस्पिटल को लेकर सोशल मीडिया पर उठे सवालों के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि रजा हॉस्पिटल में मानकों की अनदेखी और अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच टीम गठित की। टीम द्वारा अस्पताल के दस्तावेज, लाइसेंस और चिकित्सा सुविधाओं की बारीकी से जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जिले में बिना लाइसेंस संचालित अस्पताल, फर्जी डिग्री धारक डॉक्टर, मानकविहीन नर्सिंग होम, ग्रामीण इलाकों में चल रहे अवैध क्लीनिक, पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर प्रशासन की रडार पर हैं। इन संस्थानों पर लंबे समय से आम जनता का शोषण करने के आरोप लगते रहे हैं।

सम्पूर्ण समाधान दिवस में डीएम-एसपी ने सुनीं जनसमस्याएं, त्वरित निस्तारण के निर्देश

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में माह अप्रैल के तृतीय शनिवार को तहसील कादीपुर सभागार में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने की, जबकि पुलिस अधीक्षक चारु निगम एवं मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह भी उपस्थित रहे।

सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने जन सामान्य की समस्याओं एवं शिकायतों को गम्भीरता पूर्वक सुना। विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों पर मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन

को राहत मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि जनता की समस्याओं का शीघ्र एवं पारदर्शी समाधान हो। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। इस अवसर पर राजस्व, पुलिस, विकास एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए सक्रियता दिखाई।

मांगी नाव न केवट आना, कहहि तोहार मरम मै जाना

लम्भुआ/सुल्तानपुर। स्थानीय क्षेत्र के चौकिया गाँव में नव दिवसीय संगीतमयी श्रीराम कथा के अष्टम दिवस राम केवट संवाद, भरत चरित्र कथा के साथ राम वन गमन की कथा का मार्मिक वर्णन पंडित राकेश जी महराज द्वारा किया गया। आठवे दिन की रामकथा को आगे बढ़ाते हुए महाराज की ने माँ कैकेई द्वारा राजा दशरथ से तीन वर के रूप में राम को 14 वर्ष के वनवास की मांग और पिता के आदेश पर राम का माँ जानकी और लक्मण के साथ वन गमन का वर्णन किया। भगवान राम और निषाद राज केवट के संवाद ' मांगी नाव न केवट आना, कहहि तोहार मरम मै जाना'... का भावपूर्ण विस्तार पूर्ण कथा को सुनाया। कथा के मध्य पंडित राकेश जी द्वारा भरत चरित्र की कथा सुन पंडाल में मौजूद सैकड़ो रामकथा प्रेमी भाव विभोर हो उठे। मुख्य यजमान राम जन पाण्डेय और विमला देवी द्वारा आरती की गई।

अफसरों में रार : 'करोड़ों की जमीन घोटाला, गिफ्ट में लिया 1.75 लाख का आईफोन', तबादले के बाद तहसीलदार ने खोले राज

आर्यावर्त संवाददाता

फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के टूंडला की तहसीलदार राखी शर्मा ने अपने तबादले के बाद जिले के एक शीर्ष अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारियों के खिलाफ बृहस्पतिवार रात मोर्चा खोल दिया। तहसीलदार ने प्रेसवार्ता कर उक्त शीर्ष अधिकारी पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए। साथ ही देर रात टूंडला के रंजीत गुप्ता पर प्राथमिकी दर्ज कराई।

तहसीलदार के आरोपों के जवाब में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ लामबंद हो गया और तहसीलदार के दावों को झूठा करार देते हुए उनके खिलाफ मंडलायुक्त से कार्रवाई की मांग की। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

बृहस्पतिवार को तहसीलदार राखी शर्मा का स्थानांतरण टूंडला से शिकोहाबाद तहसील में कर दिया गया। तबादले का आदेश मिलते ही राखी शर्मा ने देर रात प्रेसवार्ता कर उच्चाधिकारियों पर हमला बोल दिया। दावा किया कि उनके खिलाफ एक

विभागीय जांच को रफा-दफा करने के एवज में 1.75 लाख रुपये का आईफोन रिश्वत के तौर पर लिया गया। तहसीलदार ने आला अधिकारियों के साथ-साथ उनके करीबियों पर भी मानसिक शोषण का आरोप मढ़ा। तहसीलदार ने जिले में बड़े स्तर पर चल रहे कथित जमीन घोटाले का आरोप लगाया।

कहा, जिले में बाबुओं और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये की सरकारी जमीनों की बंदरबांट की गई है। इसे जनपद का सबसे बड़ा भू-घोटाला बताते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई।

प्रशासन ने जारी की बेनाम सफाई बयान देने से बच रहे हैं अधिकारी

तहसीलदार राखी शर्मा के आरोपों को जिला प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर निराधार और तबादले से उपजा आक्रोश करार दिया है। हालांकि प्रशासन ने जो सफाई जारी की है, उसमें जारीकर्ता का नाम-पदनाम नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, राखी शर्मा का स्थानांतरण 16 अप्रैल 2026 को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत अन्य तहसीलदारों के साथ किया गया था।

प्रशासन का कहना है कि वह लगातार शासकीय कार्यों में लापरवाही बरत रही थीं और राजस्व परिषद के आदेशों की अवहेलना के चलते उन्हें पहले भी प्रतिकूल प्रविष्टि दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद नोटिसों का जवाब नहीं दिया जो कर्मचारी आचरण नियमावली का सीधा उल्लंघन है।

प्रशासन का दावा है कि तहसीलदार अपने विरुद्ध चल रही जांचों को प्रभावित करने के लिए ओएसडी शीलेंद्र शर्मा और अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों पर मनगढ़ंत आरोप लगा रही हैं। वहीं, रंजीत के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज न करने का तहसीलदार का आरोप गलत पाया गया, क्योंकि पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया जा चुका है।

कर्मचारी संघ ने कमिश्नर को लिखा पत्र

तहसीलदार के इन आरोपों के बीच शुक्रवार को उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ ने तहसीलदार के दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे उनकी हताशा बताया। संघ के जिला अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने कहा कि जेए बाबू राजेंद्र खन्ना और डीएम के ओएसडी शीलेंद्र शर्मा पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। संघ ने इस संबंध में मंडलायुक्त (कमिश्नर) आगरा मंडल को पत्र लिखकर तहसीलदार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है।

रंजीत गुप्ता पर ब्लैकमेलिंग समेत कई आरोप लगाए

प्रशासनिक रार के बीच तहसीलदार राखी शर्मा ने टूंडला के ब्रजविहार कॉलोनी निवासी रंजीत गुप्ता के विरुद्ध ब्लैकमेलिंग, मानहानि और आईटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। तहसीलदार का आरोप है कि रंजित अवैध कार्यों के लिए उन पर दबाव बना रहा था और असफल होने पर सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकारी की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहा था।

आमने-सामने भिड़ीं दो बाइक, युवक की मौके पर मौत

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय/सुलतानपुर। बल्दीराय क्षेत्र के मिझूठी महादेवन में शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 30 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर से हुआ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अयोध्या जिले के इनायत नगर थाना क्षेत्र के मरेवा सेहरा निवासी रामजी मौर्य (पुत्र गंगा राम मौर्य) अपनी ससुराल गौरा बारामऊ (बल्दीराय) से मोटरसाइकिल द्वारा घर लौट रहे थे। जैसे ही वह मिझूठी महादेवन पहुंचे, सामने से आ रही एक अन्य तेज रफ्तार बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि रामजी मौर्य गंभीर रूप से घायल हो गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही बल्दीराय थाना प्रभारी महेंद्र प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं, टक्कर मारने वाला बाइक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मृतक अपने पीछे पत्नी और दो नाबालिग बच्चों को छोड़ गए हैं। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आरोपी चालक की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।

कक्षा एक से आठ तक के सभी स्कूलों का समय बदला, सुबह 7 :30 से दोपहर 12 बजे तक चलेंगी कक्षाएं

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। प्रयागराज में कक्षा एक से 8 तक के सभी स्कूलों का समय बदल गया है। 20 अप्रैल से सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। इस संबंध में डीएम की ओर से आदेश जारी किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर विद्यालयों का समय बदल दिया गया है।

भीषण गर्मी और तापमान में वृद्ध होने के साथ लू से बचाव के लिए जिले के समस्त परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्डों के कक्षा एक से आठ तक के विद्यालयों का समय सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक किया गया है। इस संबंध में सभी विद्यालयों को अवगत करा दिया गया है कि इसमें तनिक भी लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जिले में तापमान तेजी के साथ बढ़ रहा है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। यही स्थिति शनिवार को भी रही।

मिशन शक्ति का यह उद्देश्य महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन

सुल्तानपुर। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुलतानपुर में मिशन शक्ति 5.0 का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्राचार्य डॉ. प्रियांक वर्मा के मार्गदर्शन में एमबीबीएस 2025 बैच द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन एवं मिशन शक्ति 5.0 के मुख्य तीन एजेंडों की विस्तृत व्याख्या सामुदायिक चिकित्सा विभाग की सहायक आचार्य डॉ. पायल सिंह द्वारा की गई। उन्होंने महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन पर विशेष प्रकाश डाला। कार्यक्रम के समापन पर औषधि विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉ. सलिल कुमार श्रीवास्तव ने निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए छात्र-छात्राओं को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर एमबीबीएस 2025 बैच के छात्र-छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी की। छात्र आसिम एवं आराध्या ने महिला सशक्तिकरण पर प्रभावशाली कविता प्रस्तुत की।

यूपी का 594 KM लंबा गंगा एक्सप्रेसवे : वाहन चलेंगे और उतर सकेंगे विमान, न नींद न थकान, बचेगा समय सफर होगा आसान

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। गंगा एक्सप्रेसवे का रन ट्रायल पूरा कर लिया गया है। पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाले 594 किमी लंबे इस एक्सप्रेसवे का सफर खूबियों से भरा होगा। जीरो रिस्क वाले इस लंबे सफर में वाहन चालकों को न नींद आएगी न थकान। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का हरदोई के सलेमपुर में लोकार्पण करेंगे।

इस एक्सप्रेसवे पर कई आधुनिक सार्वजनिक सुविधाएं मिलेंगी। इनमें विश्राम स्थल, चिकित्सा सेवा, आपात स्थिति के लिए ट्रॉमा सेंटर और भोजनालय भी शामिल हैं। एक्सप्रेसवे के किनारे रंबल स्ट्रिप्स लगाई गई हैं, जो वाहनों के गुजरने पर कंपन पैदा करेंगी। इससे चालकों को सचेत किया जा सकेगा। रंबल स्ट्रिप लंबे सफर में वाहन चालकों को थकान नहीं होने देगी। इससे थकान के कारण होने

वाले हादसों के खतरे को कम किया जा सकेगा।

मेरठ से प्रयागराज के बीच 15 टोल प्लाजा

यूपीडा के अधिशासी अभियंता राकेश के अनुसार मेरठ से प्रयागराज के बीच 15 टोल प्लाजा पर कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। साइनबोर्ड लगा दिए गए हैं और स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम सक्रिय कर दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत मेरठ-हापुड़ रोड स्थित गांव बिजौली से होगी।

यहां से चार किमी दूर खड़खड़ी में पहला टोल भरना होगा। हालांकि इस एक्सप्रेसवे पर लगे टोल पर रुकना नहीं पड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। पूरे एक्सप्रेसवे सीसीटीवी कैमरों की नजर में है।

चप्पे-चप्पे पर कैमरों की निगरानी होगी। अगर कोई भी व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करता है या फिर वाहनों से स्टंट और आपराधिक गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो वह कैमरे में कैद हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे जनता के लिए पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।

गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। सीसीटीवी कैमरे, पथ प्रकाश, हरियाली, टोल प्लाजा सभी सुविधाओं से एक्सप्रेसवे लैस हो गया है। उद्घाटन के बाद वाहन फर्राटे भरने लगेंगे।

- राकेश मोगा, अधिशासी अभियंता, यूपीडा।

वाहन चलेंगे और उतर सकेंगे विमान

गंगा एक्सप्रेसवे पर केवल वाहन ही नहीं दौड़ेंगे, बल्कि आपातकाल की स्थिति में लड़ाकू विमानों को भी उतारा जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे पर चार स्थानों पर विमानों के उतरने के लिए हवाई पट्टियां बनाई गई हैं। इनमें से शाहजहांपुर के जलालाबाद में 3.5 किलोमीटर लंबी पट्टी तैयार की गई है। एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार की सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटे रखी है।

उद्घाटन से एक दिन पहले ही हटेंगे मिट्टी के ढेर

गंगा एक्सप्रेसवे के बिजौली में मेरठ-हापुड़ सड़क पर बनाए गए इंटरचेंज के सभी मार्ग मिट्टी डालकर बंद किए गए हैं। जिनको उद्घाटन से एक दिन पहले ही मिट्टी हटाकर खोला जाएगा। इससे पहले एक्सप्रेसवे पर किसी को पैदल चलने या अपने वाहन दौड़ाने की अनुमति नहीं है। इसके बाद भी वाहनों की गति 120 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी।

यूपी में जन्म से स्नातक तक सरकार का साथ, राज्य की 27 लाख बेटियों को मिल रही 25000 की नई सौगात

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 'आधी आबादी' के उत्थान और सशक्तिकरण के संकल्प को एक नई दिशा मिल रही है। राज्य सरकार की फ्लैगशिप 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' बेटियों के लिए जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक का आर्थिक सुरक्षा कवच बन चुकी है। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना ने अब तक प्रदेश की 27 लाख से अधिक बालिकाओं के जीवन में नई रोशनी भरी है, जो योगी सरकार की व्यापक पहुंच और महिला सशक्तिकरण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है।

साल 2019 में शुरू हुई इस क्रांतिकारी योजना के तहत अब तक 27,37,676 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 674.13 करोड़ की भारी-भरकम धनराशि सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी है। बालिका के जन्म से लेकर स्नातक में प्रवेश तक कुल छह चरणों में दी जाने वाली यह आर्थिक सहायता बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रख रही है।

यह योजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति दशकों पुरानी संकीर्ण सोच को बदलने में भी निर्णायक भूमिका निभा रही है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के लक्ष्यों को जमीन पर उतारते हुए, यह योजना लिंगानुपात में सुधार, कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश और बालिकाओं के बेहतर स्वास्थ्य व शिक्षा को सुनिश्चित कर रही है। शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित होने के कारण, यह योजना हर घर की लाड़ली को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावी साबित हो रही है।

पात्रता की शर्तें और पारदर्शी प्रक्रिया

योजना का लाभ समाज के वास्तविक पात्रों तक पहुँचाने के लिए सरकार ने स्पष्ट मानक तय किए हैं। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख होनी चाहिए और लाभार्थी परिवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। डिजिटल पारदर्शिता के लिए mksy.up.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है। विशेष परिस्थितियों जैसे जुड़वा बच्चों या अनाथ बालिकाओं को गोद लेने के मामलों में भी सरकार ने नियमों में उदारता बरतते हुए अधिकतम तीन संतानों तक लाभ का प्रावधान किया है।

छह चरणों का प्रगति पथ

योजना के तहत कुल 25,000 की सहायता छह महत्वपूर्ण पड़ावों पर दी जाती है। पहले चरण में जन्म पर 5,000 से लेकर टीकाकरण, स्कूल प्रवेश और अंततः स्नातक या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पर 7,000 की राशि प्रदान की जाती है। महिला कल्याण निदेशालय की डायरेक्टर डॉ. वंदना वर्मा के अनुसार, सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र लाभार्थियों का समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि कोई भी बेटी अपने अधिकार से वंचित न रहे।

साउथ अफ्रीका से लौटा संदिग्ध आतंकी, दिल्ली एयरपोर्ट से पुलिस ने दबोचा, जारी था लुक आउट सर्कुलर

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। दिल्ली एयरपोर्ट पर शनिवार को साउथ अफ्रीका से लौटते ही संदिग्ध आतंकी मैजुअल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी था। मॉड्यूल से जुड़े दो संदिग्ध आतंकी अभी भी विदेश में हैं। वह दोनों सऊदी अरब में हैं। उनकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रक्रिया जारी है।

एटीएस ने दो अप्रैल को राजधानी लखनऊ से संदिग्ध आतंकियों के मॉड्यूल का खुलासा किया था। मेरठ निवासी साकिब, अरबाब और गौतमबुद्धनगर के लोकेश व विकास को गिरफ्तार किया था। एटीएस की तफ्तीश में खुलासा हुआ था कि पिछले साल नवंबर में इंस्टाग्राम लाइव का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें एके-47 और हैंड ग्रेनेड का प्रदर्शन किया गया था।

वीडियो में साकिब के अलावा दुबई में बैठे आकिब, आजाद, बिजनौर निवासी मैजुअल व अन्य लोग भी थे। इस केस में बिजनौर पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा चुकी थी। जब एटीएस ने खुलासा किया तो वह पुराना केस फिर से खोला गया। इसके बाद उवैद मलिक, जलाल हैदर और समीर को जेल भेजा गया था। मैजुल साउथ अफ्रीका में था। मैजुल, साकिब व आजाद के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किए गए थे। एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर मैजुल के पहुंचते ही उसकी गिरफ्तारी की गई। बिजनौर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में उसने आकिब के संपर्क में होने की बात स्वीकारी है। अब केस से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द सभी गिरफ्त में होंगे।

फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्लॉट बेचने के नाम पर ठगी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। पीजीआई थाना क्षेत्र में प्लॉट के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करते हुए रुपये हड़पने के मामले में पुलिस ने लंबे समय से वांछित चल रहे एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है और उसे न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।पुलिस के अनुसार यह मामला 9 जनवरी 2025 का है, जब वादिनी गायत्री देवी, निवासी बेहटा नथई सिंह, कोरारी कला, जनपद उन्नाव ने थाना पीजीआई में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गौरव अवस्थी और अन्य व्यक्तियों ने मिलकर उन्हें प्लॉट बेचने के नाम पर धोखे में रखकर उनसे रुपये हड़प लिए। आरोप है कि अभियुक्तों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्लॉट का सौदा दिखाया और इस तरह धोखाधड़ी की। इस मामले में थाना पीजीआई में मु0अ0सं0 14/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।मामले की विवेचना के दौरान थाना पीजीआई पुलिस टीम लगातार अभियुक्त की तलाश में जुटी हुई थी। इसी क्रम में पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश करते हुए वृन्दावन योजना क्षेत्र में मौजूद थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि वांछित अभियुक्त सेक्टर-14 स्थित नहर पुलिया के पास एक कार्यालय में मौजूद है। सूचना को विश्वसनीय मानते हुए पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और मुखबिर के इशारे पर एक व्यक्ति को पकड़ लिया।

72 घंटे में खुला 1180 बोरी पीओपी ठगी कांड : फर्जी फर्म मालिक बनकर ट्रक चालक को झांसा देने वाले तीन शातिर गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। गोसाईगंज थाना क्षेत्र में फर्जी फर्म मालिक बनकर ट्रक चालक को गुमराह करते हुए ट्रक में लदी 1180 बोरी पीओपी उतरवा लेने की बड़ी ठगी की घटना का पुलिस ने मात्र 72 घंटे के भीतर सफल अनावरण कर दिया। संयुक्त पुलिस टीम ने घटना में शामिल तीन शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से पूरी 1180 बोरी पीओपी, घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिलें और चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है।यह कार्रवाई लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस उपायुक्त दक्षिणी अमित कुमार आनंद, अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी रल्लापल्ली बसंथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज ऋषभ यादव के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक डी.के. सिंह और प्रशिक्षु आईपीएस सारिका चौधरी के नेतृत्व में थाना गोसाईगंज और सर्विलांस टीम जोन दक्षिणी की संयुक्त टीम ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया।पुलिस के अनुसार 4 अप्रैल 2026 को ट्रक चालक बलराज सिंह, निवासी ग्राम ठूठयावाली कैच्चया जनपद मनसा, पंजाब, दंतौर से पीओपी (सकरनी ब्रांड) की 1180 बोरियां लादकर बाराबंकी स्थित एक फर्म में पहुंचाने के लिए रवाना हुआ था। जब ट्रक गोसाईगंज क्षेत्र में पहुंचा, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर स्वयं को संबंधित फर्म का मालिक बताया और चालक को निर्देश दिया कि माल बाराबंकी न ले जाकर गोसाईगंज में ही उतार दिया जाए।कुछ देर बाद दूसरे मोबाइल नंबर से कॉल कर खुद को फर्म का मुंशी बताने वाले व्यक्ति ने चालक से संपर्क किया और माल उतरवाने के लिए आने की जानकारी दी। इसके कुछ समय बाद तीन युवक डाला और ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर मौके पर पहुंचे और चालक को विश्वास में लेकर ट्रक में लदी सभी 1180 बोरी पीओपी उतरवा ली। इसके बाद अभियुक्तों ने माल को ग्राम कबीरपुर स्थित किराये के एक कमरे में रखवा दिया और मौके से फरार हो गए।बाद में जब माल भेजने वाली कंपनी ने भिलवल स्थित फर्म से संपर्क किया तो माल न पहुंचने की जानकारी मिली। इसके बाद ट्रक चालक से पूछताछ की गई, जिसमें उसने बताया कि उसने फर्म मालिक के निर्देश पर गोसाईगंज में माल उतार दिया था। इस पर संदेह होने पर जब संबंधित मोबाइल नंबरों पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो सभी नंबर बंद मिले। तब चालक को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का एहसास हुआ और उसने 14 अप्रैल 2026 को थाना गोसाईगंज में मुकदमा दर्ज कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल दो विशेष टीमों का गठन किया।

संक्षेप

बेहटा चौराहे पर दर्दनाक सड़क हादसा : कार-बाइक की टक्कर में युवक की मौत, चालक हिरासत में

लखनऊ। काकोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेहटा चौराहा पर शनिवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल व्याप्त हो गया, वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंच गई।प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दिनांक 18 अप्रैल 2026 को समय लगभग 11:00 बजे बेहटा चौराहे पर एक कार (संख्या UP 32 JW 8720, ईऑन) और मोटरसाइकिल के बीच आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल सवार आशीष यादव (उम्र लगभग 40 वर्ष), निवासी ग्राम बेहटा, थाना काकोरी, गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और घायल को बचाने के प्रयास शुरू किए।सूचना मिलते ही एंबुलेंस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल आशीष यादव को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरोजिनी नगर ले जाया गया। वहां मौजूद चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और अस्पताल परिसर में शोकपूर्ण माहौल बन गया।घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच शुरू की। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल कार को कब्जे में ले लिया है तथा कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मृतक के शव का पंचायतनामा भरने की कार्रवाई की जा रही है और परिजनों की मौजूदगी में अग्रिम विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।पुलिस के अनुसार मामले में तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। प्रारंभिक जांच में सड़क दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि मामले में सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

SC में सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थी लखनऊ में फिर दिखाएंगे दम, परिजन भी होंगे शामिल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 22 अप्रैल को फिर से राजधानी लखनऊ में दम दिखाएंगे। इस बार अभ्यर्थियों के साथ-साथ उनके परिजन भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। वहीं इस मामले में अलग-अलग आंदोलन कर रहे संगठन भी एकजुट होंगे। अभ्यर्थियों ने बताया कि उनका दो फरवरी से राजधानी के ईको गार्डन में अनवरत धरना चल रहा है। किंतु सरकार इस मामले में चुप्पी साधे बैठी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार कोई पहल नहीं कर रही। इससे मामला टलता जा रहा है। इस प्रकरण की पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2024 में हुई थी। उसके बाद से लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता ने कहा कि पिछली सुनवाई 19 मार्च को होनी थी लेकिन हुई नहीं। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में अनलिस्टेड है। इससे सभी अभ्यर्थियों में बहुत आक्रोश है। हमने 22 अप्रैल को महाआंदोलन करने का फैसला लिया है। सुशील कश्यप ने बताया कि सभी जिले में समन्वयक बनाकर ब्लाक स्तर पर सम्पर्क किया जा रहा है। ताकि अभ्यर्थियों के साथ उनके परिजन भी आ सकें। आंदोलन में शामिल सुमित कुमार, विक्रम, अमित मौर्या आदि ने कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट और लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला, सब हमारे पक्ष में है। फिर भी हमारे साथ न्याय इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम पिछड़े समाज से आते हैं। सरकार जल्द इस मामले में ठोस पहल नहीं करती है तो आंदोलन व्यापक होगा।

स्वधर्म स्वदेश स्वराज्य हमारे स्वबोध की प्रेरणा : स्वान्त रंजन

लखनऊ। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के युवा शोधार्थी आयाम की ओर से शनिवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में 'आत्मबोध से विश्वबोध' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख स्वान्त रंजन ने कहा कि स्वधर्म, स्वदेश और स्वराज्य हमारे स्वबोध की प्रेरणा है। इसके आधार पर ही महापुरुषों व क्रान्तिकारियों ने समाज जागरण करने का काम किया। उन्होंने कहा कि देश में राष्ट्रभाव को कमजोर करने,एकात्मभाव कैसे बिखर जाय व धर्म के आधार पर देश में जो एकसूत्रता है उसको विखण्डित करने का प्रयत्न योजनाबद्ध ढ़ंग से किया गया। अंग्रेजों ने जानबूझकर भारत के इतिहास को विकृत करना प्रारम्भ किया। जो कभी भारत आये नहीं ऐसे तथाकथित इतिहासकारों से भारत का इतिहास लिखवाया गया। स्वान्त रंजन ने कहा कि संस्कृति राष्ट्र की आत्मा होती है। देश को एकजुट रखने में संस्कृति महत्वपूर्ण कड़ी है। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख ने कहा कि लगातार इस्लामिक आक्रमणों के कारण हिन्दू समाज आत्मविस्मृत हो गया था। समाज आत्मकेन्द्रित हो गया था। ऐसे समय में डा.केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। स्व का विचार करते हुए सामाजिक समरसता के आधार पर सभी जाति वर्ग को सशक्त करना है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डा. पवनपुत्र बादल ने कहा कि सनातन परम्परा के विचारों को हम जीते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की पूरी साहित्य परम्परा में भारत बोध है।

दिल्ली के विवादित विश्वविद्यालय के छात्रों और सियासी दल ने मजदूरों को भड़काया, जांच में खुलासा

लखनऊ। नोएडा में हुए बवाल को भड़काने के पीछे दिल्ली के एक विवादित विश्वविद्यालय के छात्रों और एक सियासी दल के लोगों का हाथ था। जांच के दायरे में आए सियासी दल का जुड़ाव कुछ नक्सली संगठनों से भी है। शासन के निर्देश पर इस मामले की जांच कर रही एसटीएफ की जांच में इसके पुख्ता सुराग हाथ लगे हैं। एसटीएफ इसमें शामिल लोगों को तेजी से चिन्हित कर रही है। जल्द ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, नोएडा में बवाल शुरू होने के बाद दिल्ली के एक विश्वविद्यालय के छात्रों का एक गुट वहां पहुंचा, जिसने मजदूरों के गुस्से को भड़काया। इस गुट ने ही गाड़ियों में आग लगाई और पुलिस को निशाना बनाया। इसके अलावा एक राजनीतिक दल के समर्थक भी उनके साथ नोएडा गए थे, जिन्होंने मजदूरों को हिंसा के लिए उकसाया था। पुलिस की सख्ती बढ़ने पर उन्होंने वापस दिल्ली का रुख किया लेकिन कुछ मेट्रो स्टेशन से उन्हें दबोच लिया गया। पूछताछ में उन्होंने कबूला कि उनका मकसद मजदूरों के प्रदर्शन को हिंसक रूप देना था।

एफडीडीआई फुरसतगंज में लेदर लाइफस्टाइल एंड प्रोडक्ट डिजाइन का नया कोर्स शुरू

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर भारत के छात्रों को अब फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एफडीडीआई), फुरसतगंज में एमबीए के साथ ही बी.डेस. जैसे डिजाइनिंग क्षेत्र में करियर बनाने के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। इसी कड़ी में संस्थान द्वारा इस वर्ष लेदर लाइफस्टाइल एंड प्रोडक्ट डिजाइन का नया कोर्स प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को प्रवेश दिया जाएगा।यूपी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में संस्थान के कार्यकारी निदेशक सुनील कुमार द्विवेदी ने बताया कि इस सत्र में बढ़ती मांग को देखते हुए लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज डिजाइन नामक नया विभाग शुरू किया जा रहा है। इसके तहत संस्थान डिजाइन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे फुटवियर, फैशन तथा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट डिजाइनिंग में रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है।उन्होंने बताया कि 100 प्रतिशत प्लेसमेंट की सुविधा के कारण संस्थान लगातार प्रगति कर रहा है। द्विवेदी ने विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि जो छात्र इस वर्ष 12वीं या स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं और रोजगारपरक पाठ्यक्रम की तलाश में हैं, उन्हें एफडीडीआई द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों पर अवश्य विचार करना चाहिए।उन्होंने जानकारी दी कि पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क लखनऊ-हरदोई क्षेत्र में स्थापित हो रहा है, जबकि कानपुर और उन्नाव में नया फुटवियर पार्क बनाया जा रहा है। इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।कार्यकारी निदेशक ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी पीएम विद्यालक्ष्मी शैक्षिक ऋण योजना का लाभ ले सकते हैं। फुरसतगंज परिसर इस ऋण योजना के लिए पंजीकृत संस्थानों में शामिल है। इसके अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के छात्र उत्तर प्रदेश फीस प्रतिपूर्ति योजना का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।

आरटीई के जरिये 1 लाख से अधिक बच्चों को मिला निजी स्कूलों में दाखिला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 में अब तक एक लाख से अधिक बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला मिल चुका है। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार, नामांकन प्रक्रिया जारी है और आने वाले चरणों में यह संख्या और बढ़ेगी। शनिवार को यहां जारी एक सरकारी बयान में आंकड़ों के हवाले से कहा गया कि नामांकन में लखनऊ सबसे आगे है, जहां 7,952 बच्चों को दाखिला मिला है। इसके बाद वाराणसी में 4,957, बुलंदशहर में 4,154 और बदायूं में 3,599 बच्चों का नामांकन हुआ है। मुरादाबाद, आगरा, कानपुर नगर, गोरखपुर, अलीगढ़ और गाजियाबाद भी शीर्ष 10 जिलों में शामिल हैं। बयान के अनुसार सरकार का कहना है कि आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा का अवसर मिल रहा है।

विश्व धरोहर दिवस पर मंत्री ए. के. शर्मा ने किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने मऊ स्थित मंगलम भवन परिसर में पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों से अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की।मंत्री ए. के. शर्मा ने कहा कि पेड़-पौधे मानव जीवन के आधार हैं, क्योंकि यही हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपने जीवन में अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी नियमित देखभाल का संकल्प लें।उन्होंने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण से ही शुद्ध वायु मिलती है और शुद्ध वायु से ही स्वस्थ जीवन संभव है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही समाज और राष्ट्र के विकास में प्रभावी योगदान दे सकता है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण को जन-आंदोलन का रूप देना आवश्यक है।मंत्री ने यह भी कहा कि पर्यावरण हमारी अमूल्य धरोहर है, जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है। यह केवल सरकार की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।इस अवसर पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

डीएनए एवं जैविक साक्ष्य संकलन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित, वैज्ञानिक विवेचना को मिलेगा बढ़ावा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के प्रति दक्ष बनाने के उद्देश्य से "डीएनए एवं अन्य जैविक साक्ष्य संकलन" विषय पर एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला 18 अप्रैल 2026 को रिजर्व पुलिस लाइन, लखनऊ स्थित संगोष्ठी सदन में सफलतापूर्वक संपन्न हुई।कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) बबलू कुमार तथा पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) अमित कुमावत के प्रभावी मार्गदर्शन में किया गया। कार्यशाला का सफल संचालन सहायक पुलिस आयुक्त (महिला अपराध/ट्रेनिंग सेल) सौम्या पाण्डेय के पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ।इस प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से साक्ष्य संकलन, संरक्षण एवं उनके प्रभावी उपयोग के प्रति प्रशिक्षित करना था, ताकि अपराधों की विवेचना अधिक सटीक, निष्पक्ष एवं परिणामोन्मुख बनाई जा सके। कार्यक्रम में कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थाना क्षेत्रों से नामित 107 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिन्हें विशेषज्ञों द्वारा व्यवहारिक एवं तकनीकी दोनों स्तरों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।प्रशिक्षण सत्र में विशेषज्ञ प्रशिक्षक के रूप में विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ की वैज्ञानिक अधिकारी प्रगति सिंह ने प्रतिभागियों को डीएनए एवं अन्य जैविक साक्ष्यों के संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी दी।

सरोजनीनगर में महिला से दुष्कर्म व लूट का 24 घंटे में खुलासा, शातिर आरोपी गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। सरोजनीनगर थाना क्षेत्र में महिला के साथ दुष्कर्म और लूट की गंभीर घटना का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 1.15 लाख रुपये मूल्य की ज्वैलरी भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि आरोपी पूर्व में जिला बदर भी रह चुका है और उसके विरुद्ध कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।पुलिस के अनुसार 16 अप्रैल 2026 को वादी द्वारा थाना सरोजनीनगर में तहरीर देकर सूचना दी गई कि 15 अप्रैल 2026 को उसकी पत्नी, जो 14 अप्रैल को नशे की हालत में थी, दरोगाखेड़ा शराब ठेका के पास एक युवक के संपर्क में आई। आरोप है कि उक्त युवक उसे अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सरोजनीनगर में तत्काल मु0अ0सं0 140/2026 धारा 64(1) बीएनएस के तहत अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में पीड़िता के बयान के आधार पर लूट की घटना सामने आने पर धारा 309(4) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य संकलन और छानबीन के आधार पर अभियुक्त अभिमन्यु राजपूत उर्फ मन्ना लोधी, निवासी दरोगाखेड़ा थाना सरोजनीनगर, का नाम प्रकाश में लाया। इसके बाद पुलिस टीम ने 17 अप्रैल 2026 को रानीपुर कट के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय उसके कब्जे से लूटी गई ज्वैलरी बरामद की गई, जिसके बाद मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की भी बढ़ोत्तरी की गई।पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त अभिमन्यु राजपूत उर्फ मन्ना (उम्र करीब 27 वर्ष) शातिर किस्म का अपराधी है, जो पूर्व में लूट, मारपीट और अवैध शस्त्र रखने जैसे मामलों में संलिप्त रहा है। उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए न्यायालय द्वारा 7 सितंबर 2025 से छह माह के लिए उसे जिला बदर घोषित किया गया था। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद उसने पुनः गंभीर अपराध को अंजाम दिया।पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से एक जोड़ी पायल, एक जोड़ी बिछिया तथा पीली धातु के कान के टप्स बरामद किए हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 1.15 लाख रुपये बताई गई है।पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्रवाई में वरिष्ठ उपनिरीक्षक हरद्वारी लाल, उपनिरीक्षक उत्कर्ष त्रिपाठी, उपनिरीक्षक अमरजीत मिश्रा तथा उपनिरीक्षक आशीष कुमार की टीम शामिल रही।

बिहार में नीतीश कुमार, एक विकास युग का सम्मानजनक अंत

भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री का कार्यकाल इतने सम्मान से समाप्त हुआ हो जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेवा निवृत्ति हुई है। नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने थे और आज यानि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ इतीफा दिया है ।वे 20 वर्ष से अधिक समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहे है। आरंभ उनकी समता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन था ।वह दौर भाजपा में अटलजी, आडवाणी जी का था।2010 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को दो तिहाई सीट मिली लेकिन मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार

2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैचारिक मतभेद चलते राजद के साथ लड़े और विधानसभा चुनाव में बहुमत भी लाए ।2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर चुनाव जीते लेकिन उनकी 47 सीट आई जबकि भारतीय जनता पार्टी की 77 विधायक चुनकर आए लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू भाजपा, लोजपा के साथ मिलकर 39 सीट कुल 40 में से जीती ।2025 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 89, जेडीयू,85, लोजपा 19, जीतनराम माझी को 6 सीट मिली।राजद का सूपड़ा साफ हो गया। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने।यानि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 04 बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आज उन्होंने राज्य सभा में जाने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।बताया जाता है कि 75 वर्षीय नीतीश कुमार का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है यही मुख्य कारण है। नीतीश कुमार ने यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शेयर कर पद मुक्ति बात रखी ।

नीतीश कुमार ने 2005 में जब पद सम्हाला था तब उन्हें बीमार राज्य मिला था। चारों ओर लूट, अपराध, अपहरण,सरकारी डकैती,ठेका पर कब्जा ,राजद की गुंडागर्दी, महिलाओं से जुड़े अपराध, औद्योगिक विकास समाप्त जैसे वातावरण था ।सड़क टूटी फूटी, गड्ढे, बुनियादी ढांचे में कोई विकास नहीं था । ऐसे में नीतीश कुमार ने राज्य को खड़ा किया। अपराध मुक्त कराया। संगठित अपराधियों जेल में ठूसा।

नीतीश कुमार की सम्मान जनक बिदाई दी गई है वरना नरेंद्र मोदी के अलावा किसी ने अपने मन मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा है। नरेंद्र मोदी ने भी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले कर मुख्यमंत्री पद छोड़ा था।भारत के राजनीतिक इतिहास में

गोविंदबल्लभ पंत,कामराज नाडार, जयललिता, करुणानिधि, हेमवती नंदन बहुगुणा, सुचेता कृपलानी, मोहन लाल सुखाड़िया, मुलायम सिंह, सरीखे मुख्यमंत्री रहे।

बिहार के नालंदा जिले केबखियार पुर नामक गांव से कुर्मी जाति में जन्मे नीतीश कुमार के पिता वैद्य थे । नीतीश कुमार ने बहुत

विख्यात पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़कर बी ई मैकेनिकल की डिग्री प्राप्त की उसके बाद वे राज्य इलेक्ट्रिकी बोर्ड में सहायक यंत्री बने लेकिन उनका मन राजनीति में रमता था।इस लिए वे जयप्रकाशनायरण के संपर्क में आए और राजनीत शुरू की ।1977 में वे लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए। उसके बाद अटलजी की सरकार में कृषि, रेल, मंत्री रहे और 2005 में मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार का जीवन बहुत सुचिता पूर्ण रहा । नीतीश कुमार पर 20 वर्ष के मुख्यमंत्री तौर पर भ्रष्टाचार,भाई भतीजा बाद, पुत्र बाद का आरोप नहीं लगा है।जब वे अटलजी की सरकार 6वर्ष कबिनेट मंत्री रहे तब भी बहुत ही बेहतर कार्य किया था।

भारत की औषधि रणनीति पैमाने से नवाचार की ओर बढ़ रही है

जगत प्रकाश नड्डा

केंद्रीय बजट 2026-27 में ?10,000 करोड़ के मिशन बायोफार्मा निर्माण शक्ति की घोषणा इस दिशा में एक निर्णायक कदम को रेखांकित करती है।

वैश्विक स्तर पर, कुल औषधि राजस्व में बायोलॉजिक, बायोसिमिलर और विशेष दवाओं की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक हो गयी है। लंबे समय से जेनरिक दवाओं में अग्रणी देश होने के कारण 'विश्व की फ़ार्मेसी' के रूप में प्रसिद्ध भारत का औषधि उद्योग अब पैमाने से नवाचार की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत सरकार भविष्य के अनुरूप एक नीतिगत रूपरेखा को गति दे रही है, ताकि देश जेनरिक दवाओं में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखते हुए इन उभरते क्षेत्रों में अधिक हिस्सेदारी प्राप्त कर सके।

केंद्रीय बजट 2026-27 में ?10,000 करोड़ के मिशन बायोफार्मा निर्माण शक्ति की घोषणा इस दिशा में एक निर्णायक कदम को रेखांकित करती है। यह अगले 8 से 10 वर्षों में भारत को बायोफार्मा नवाचार और उच्च मूल्य वाली चिकित्सा सेवाओं के वैश्विक केन्द्र बनाने के देश के संकल्प का संकेत देती है। यह विज़न गहरी वैज्ञानिक क्षमताओं के निर्माण, नवाचार-आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने और भारत को अगली पीढ़ी की दवाओं के क्षेत्र में एक अग्रणी देश के रूप में उभरने में सक्षम बनाने पर आधारित होगा।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर और उन्नत चिकित्सीय क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं को गति देना है। यह कार्यक्रम औषधि विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की मौजूदा पहलों का पूरक है, जैसे फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना (पीआरआईपी), अनुसंधान विकास और नवाचार योजना, बायोनेस्ट आदि, जिनका उद्देश्य जैव- औषधि समेत जीवन विज्ञान क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। ये पहलें भारत के नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने, उद्योग-अकादमी सहयोग को बढ़ावा देने तथा जेनेरिक दवाओं से नवाचार संचालित दवा अनुसंधान और विकास की ओर बदलाव को सक्षम करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ किण्वन-आधारित निर्माण क्षमताओं का विकास करना है। एंटिबायोटिक, वैक्सीन, एंज़ाइम और बायोलॉजिक्स के निर्माण में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, यह क्षेत्र लंबे समय से आयात पर निर्भर रहा है।

अवसंरचना में निवेश करके, प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाकर तथा लक्षित प्रोत्साहन प्रदान करके, भारत इस रणनीतिक क्षेत्र में घरेलू क्षमता का निर्माण करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए काम कर रहा है।

भारत के नैदानिक अनुसंधान इकोसिस्टम का विस्तार भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। 1,000 मान्यता प्राप्त नैदानिक प्रयोग केंद्र स्थापित किये जायेंगे, जो वैश्विक दवा विकास गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति को बेहतर बनायेंगे। अपनी लागत लाभ और कुशल शोधकर्ताओं की बढ़ती संख्या के साथ, भारत कुशल और उच्च गुणवत्ता वाले नैदानिक प्रयोग के लिए असाधारण अवसर प्रदान करता है। साथ ही, नियामक व्यवस्था को मजबूत करने और संस्थागत क्षमताओं को बढ़ाने से भारत की मौजूदा व्यवस्था वैश्विक मानकों के अधिक अनुरूप होगी, जिससे तेज अनुमोदन संभव होंगे और वैश्विक हितधारकों के बीच विश्वास बढ़ेगा।

पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने पीएलआई और थोक दवा (बल्क ड्रग) पार्क योजनाओं के सहारे सक्रिय औषधि सामग्री (एपीआई) और मुख्य आरंभिक सामग्रियों (केएसएम) के स्थानीय उत्पादन में तेज़ी से प्रगति हुई है। इससे देश में दवाओं की कीमतें घटाने में मदद मिली है, जो विश्व स्तर पर सबसे कम कीमतों में से एक है और इसके कारण नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की लागत किफायती बनी रहती है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना ने सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता युक्त जेनेरिक दवाओं तक पहुंच का विस्तार किया है, जिसके तहत 19,000 से अधिक जनऔषधि केंद्र लाखों लोगों की सेवा कर रहे हैं। कैंसर और दुर्लभ रोगों की दवाओं जैसी महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रक्रियाओं पर सीमा-शुल्क को सुव्यवस्थित करने जैसे पूरक उपाय जीवन रक्षक उपचारों तक पहुंच को और सुलभ बना रहे हैं। जैसे-जैसे उन्नत चिकित्सा प्रक्रियाएं अधिक व्यापक होंगी, किफायती दर और समान पहुंच सुनिश्चित करना केंद्रीय नीति की प्राथमिकता बनी रहेगी।

जैसे-जैसे उद्योग विकसित हो रहा है, भारत का उद्देश्य न केवल स्थापित बाजारों में बल्कि उभरते क्षेत्रों में, विशेष रूप से नवाचार-संचालित क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना है। सुधार, इस बदलाव के केंद्र में हैं। नियामक समन्वय, अनुमोदन प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और तेजी से मंजूरी जैसे प्रयास व्यापार करने में आसानी को बढ़ा रहे हैं। गुणवत्ता मानकों और नियामक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने से भारतीय औषधि उत्पादों पर वैश्विक विश्वास की निरंतरता सुनिश्चित होती है। हालांकि, आरएंडडी निवेश बढ़ाना एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। इसका समाधान करने के लिए, सार्वजनिक-निजी सहयोग को मजबूती देना आवश्यक होगा, ताकि दीर्घकालिक नवाचार को बनाए रहा जा सके।

नीतिगत समर्थन, तकनीकी प्रगति और बाजार का आपसी समन्वय; औषधि क्षेत्र के लिए विकास का एक अद्वितीय अवसर प्रस्तुत करता है। भारत का घरेलू बाजार, जिसका मूल्य पहले से ही ?4 लाख करोड़ से अधिक है, निरंतर विस्तार के लिए तैयार है। अगले दशक में, भारत न केवल जेनेरिक दवाओं में एक अग्रणी देश के रूप में, बल्कि नवोन्मेषी दवाओं, किण्वन-आधारित उत्पादों और अगली पीढ़ी की चिकित्सा-सेवाओं में भी एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में उभरने के लिए बेहतर स्थिति में है।

निष्कर्ष के तौर पर, भारत का औषधि क्षेत्र नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जो नवाचार, सुदृढ़ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा द्वारा परिभाषित होता है। बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम जैसी पहलों, नैदानिक अवसंरचना के विस्तार और लक्षित निर्माण प्रोत्साहनों के समर्थन से, भारत धीरे-धीरे मात्रा-संचालित जेनेरिक दवा केंद्र से उच्च-मूल्य वाले बायोफार्मा नवाचार अग्रणी देश की ओर आगे बढ़ रहा है। यह परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल में भारत की भूमिका को मजबूत करने और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विज़न, विकसित भारत 2047 के व्यापक लक्ष्यों को हासिल करने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा।

(लेखक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री हैं)

टिप्पणी

आखिरकार जनता पर ही बोझ

पेट्रोलियम पर उत्पाद शुल्क में कटौती से सरकारी खजाने को 2026-27 में 1.7 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा। उसकी भरपाई केंद्र कहां से करेगा? सीधा गणित है कि वह बाजार से अधिक कर्ज लेगा, जिसका बोझ आखिरकार जनता पर ही आएगा।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सत्ता होने के दौर में अपनी तिजोरी भरने वाली कंपनियों को राहत देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने उत्पाद शुल्क में भारी कटौती की है। इस कारण सरकारी खजाने को 2026-27 में 1.7 लाख करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचेगा। पिछले वर्ष सरकार ने आय कर और जीएसटी दरों में कटौती की। उससे भी उसे राजस्व का नुकसान हुआ। इन सबकी भरपाई केंद्र उसकी कहां से करेगा? सीधा गणित है कि वह बाजार से अधिक कर्ज लेगा। 2026-27 के केंद्रीय बजट में 16.09 लाख करोड़ रुपये का ऋण लेने का प्रावधान है। लेकिन अब बताया गया है कि उसका 51 फीसदी यानी 8.2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वित्त वर्ष की पहली छमाही में ही ले लिया जाएगा।

मौजूदा वित्तीय हालात को देखते हुए अनुमान है कि दूसरी छमाही कम-से-कम इतना और ऋण लिया जाएगा- यानी बजट में तय सीमा टूट सकती है। बाजार से ऋण का स्रोत अधिकांशतः ऋण का कारोबार करने वाली वित्तीय कंपनियां होती हैं। सरकारें जितना अधिक कर्ज लेती हैं, उनके बॉन्ड पर ब्याज दर उतनी बढ़ती चली जाती है। फिलहाल, भारत सरकार के दस साल के बॉन्ड की ब्याज दर 6.92 प्रतिशत है, जो हाल के किसी समय से ऊंची है। मतलब यह कि अभी के कर्ज पर सरकार की दीर्घकालिक देनदारी खासी ऊंची होगी। इस कारण हर साल कर्ज एवं ब्याज चुकाने का अधिक दबाव सरकार के बजट पर होगा।

अगर सरकार की आमदनी दूसरे स्रोतों से नहीं बढ़ेगी, तो जाहिर है, उपरोक्त देनदारी विकास एवं जन-कल्याण के खर्चों में कटौती कर पूरी की जाएगी। गौरतलब है कि परोक्ष करों के जरिए राजस्व जुटाने की गुंजाइश अब बेहद सीमित हो चुकी है। विनिवेश से पैसा जुटाने की संभावनाएं भी अब सीमित ही हैं। उस स्थिति में केंद्र के पास आमदनी बढ़ाने का एकमात्र जरिया धनी लोगों पर अधिक कर्ज लगाने का बचा है। लेकिन कॉरपोरेट्स का मुनाफा बढ़ाने की प्राथमिकता वाली वर्तमान सरकार के लिए यह सोचना भी कठिन है। इसलिए उत्पाद कर घटने का अर्थ दीर्घकाल में आम जन पर दबाव बढ़ना होगा। यही आज का गणित और हकीकत है।

ब्लॉग

वैश्विक तनाव के बीच भारत की सधी हुई चाल, ऑस्ट्रिया के साथ सहयोग बढ़ाकर मोदी ने किया कमाल

नीरज कुमार दुबे

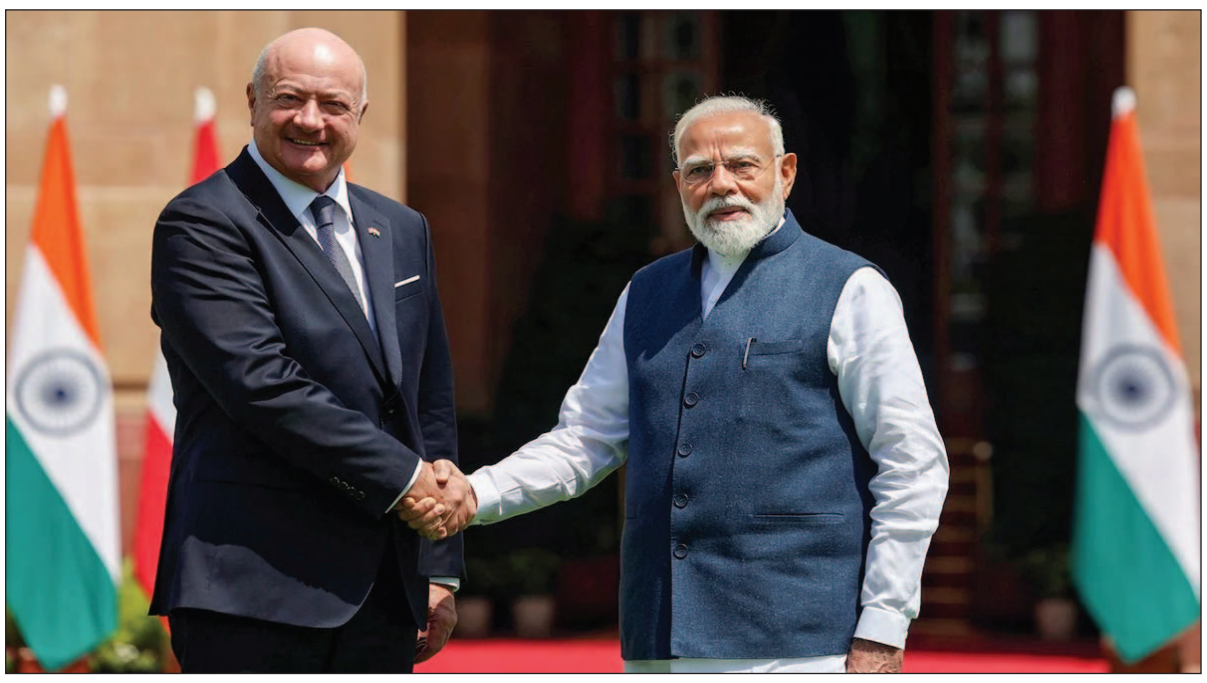

भारत और ऑस्ट्रिया के बीच संबंधों को नई दिशा देने वाली एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल के तहत ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर की भारत यात्रा ऐतिहासिक मानी जा रही है। लगभग चार दशकों के बाद किसी ऑस्ट्रियाई चांसलर का भारत आगमन न केवल द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती का संकेत है, बल्कि यह वैश्विक परिदृश्य में बदलती प्राथमिकताओं के बीच नई साझेदारी के निर्माण का भी प्रतीक है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांसलर स्टॉकर का स्वागत करते हुए इसे विशेष अवसर बताया और इस बात पर जोर दिया कि यूरोप के बाहर अपनी पहली यात्रा के लिए भारत को चुनना ऑस्ट्रिया की भारत के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के बाद आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के नए अवसर सामने आए हैं। भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध पहले से ही अवसंरचना, नवाचार और सतत विकास के क्षेत्रों में मजबूत रहे हैं। दिल्ली मेट्रो और अटल सुरंग जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में ऑस्ट्रिया की तकनीकी विशेषज्ञता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा रेलवे परियोजनाओं, रोपवे, स्वच्छ ऊर्जा और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में भी ऑस्ट्रियाई कंपनियों की सक्रिय भागीदारी रही है।

इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल पंद्रह महत्वपूर्ण समझौते और पहलें सामने आईं, जो रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, नवाचार और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों को कवर करती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्य समूह की स्थापना का प्रस्ताव, जो वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से निपटने में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करेगा।

रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग को नई गति देने के लिए सैन्य मामलों में सहयोग पर एक आशय पत्र पर सहमति बनी है। इसके तहत रक्षा उद्योग, नीति संवाद, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। यह पहल भारत और यूरोप के बीच हाल ही में हुए सुरक्षा सहयोग को भी मजबूती प्रदान करेगी। आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिससे दोनों देशों की कंपनियों और निवेशकों को आने वाली समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जा सकेगा। इससे व्यापार को सुगम बनाने और निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौता किया गया है, जिससे दोनों देशों के फिल्म उद्योग के बीच संयुक्त निर्माण और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिसके तहत वैज्ञानिक सहयोग, मानकों के आदान प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जाएगा। इससे कृषि और खाद्य उत्पादों के व्यापार को भी मजबूती मिलेगी।

इसके अलावा, दोनों देशों के बीच कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें प्रशिक्षुता प्रणाली, ज्ञान साझा करने और योग्यता की पारस्परिक मान्यता पर जोर दिया गया है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए संरचित संवाद शुरू करने और तकनीकी विश्वविद्यालयों के माध्यम से भारतीय छात्रों के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने की पहल भी की गई है।

इस यात्रा के दौरान स्टार्टअप सहयोग को बढ़ाने, साइबर सुरक्षा संवाद शुरू करने, अंतरिक्ष उद्योग में संयुक्त सेमिनार आयोजित करने और वर्किंग हॉलिडे कार्यक्रम को लागू करने जैसी घोषणाएं भी की गईं। उच्च प्रौद्योगिकी जैसे क्वांटम तकनीक, मशीन लर्निंग, जल शोधन और सामग्री विज्ञान में संयुक्त अनुसंधान को साझेदारी का मुख्य आधार बनाया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर यह भी कहा कि भारत की प्रतिभा और ऑस्ट्रिया की नवाचार क्षमता मिलकर वैश्विक स्तर पर भरोसेमंद तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला विकसित कर सकती है। उन्होंने रक्षा, सेमीकंडक्टर, जैव प्रौद्योगिकी और क्वांटम क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। इसके अलावा, मानव संसाधन के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाया है। वर्ष 2023 में हुए प्रवासन और गतिशीलता समझौते के तहत अब नर्सिंग क्षेत्र में भी सहयोग को विस्तार दिया जाएगा। युवा आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए वर्किंग हॉलिडे कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

साथ ही वैश्विक परिदृश्य पर चर्चा करते हुए दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि सैन्य संघर्ष किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। चाहे यूक्रेन का संकट हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, दोनों देशों ने स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया। साथ ही वैश्विक संस्थाओं में सुधार और आतंकवाद के पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

हम आपको एक बार फिर बता दें कि ऑस्ट्रिया भारत के लिए एक महत्वपूर्ण यूरोपीय साझेदार है। यह मध्य और पूर्वी यूरोप में प्रवेश का एक प्रमुख द्वार है और हरित प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा तथा उन्नत इंजीनियरिंग में इसकी विशेषज्ञता भारत के विकास कार्यक्रमों के लिए उपयोगी है। दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है और यह लगभग तीन अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच चुका है। देखा जाये तो भारत और ऑस्ट्रिया के बीच मजबूत होते संबंधों का प्रभाव वैश्विक भू-राजनीति पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यूरोप के मध्य में स्थित ऑस्ट्रिया, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सेतु का काम करता है, जिससे भारत को यूरोप के बाजारों, तकनीक और निवेश तक बेहतर पहुंच मिलती है। इस सहयोग से भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भूमिका और अधिक मजबूत होगी, विशेषकर उच्च प्रौद्योगिकी, रक्षा और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में। इसके साथ ही, ऑस्ट्रिया का भारत के प्रति समर्थन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को सुदृढ़ करेगा, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता जैसे मुद्दों पर। दक्षिण एशिया के संदर्भ में यह साझेदारी भारत की रणनीतिक बढ़त को और मजबूत करेगी, क्योंकि उन्नत तकनीक, रक्षा सहयोग और आर्थिक निवेश के माध्यम से भारत क्षेत्रीय नेतृत्व को और प्रभावी ढंग से स्थापित कर सकेगा। इससे न केवल भारत की सुरक्षा क्षमताएं बढ़ेंगी, बल्कि वह क्षेत्र में स्थिरता, विकास और संतुलन बनाए रखने में भी अधिक सक्षम भूमिका निभा सकेगा।

बहरहाल, ऑस्ट्रिया के चांसलर की भारत यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनों देशों के संबंध अब पारंपरिक सहयोग से आगे बढ़कर नवाचार केंद्रित और भविष्य उन्मुख साझेदारी की ओर अग्रसर हैं। दोनों देशों ने मिलकर एक ऐसे सहयोग मॉडल की नींव रखी है जो न केवल द्विपक्षीय हितों को साधेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी स्थिरता और प्रगति में योगदान देगा।

29 साल बाद इंसाफ, बचपन में हादसे में गंवाए दोनों हाथ, हाई कोर्ट का 26 लाख का मुआवजा देने का आदेश

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में करीब 3 दशक पहले बिजली विभाग की लापरवाही का शिकार हुए शख्स को अब जाकर न्याय मिला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में एक ऐसे व्यक्ति को 26।65 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसने आज से 29 साल पहले बिजली से जुड़े एक हादसे में अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे। कोर्ट ने इस केस में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को लापरवाही का दोषी ठहराया है।

जस्टिस संदीप जैन ने यह आदेश पीड़ित पप्पू की ओर से दायर पहली अपील को स्वीकार करते हुए दिया। इसके साथ ही उन्होंने 2005 के ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें पीड़ित को मुआवजा देने से इनकार कर दिया गया था। घटना मार्च 1997 की है। उस समय पीड़ित पप्पू की उम्र करीब 7 साल थी और वह आगरा के नगला पाड़ी इलाके में एक प्राइमरी स्कूल के पास लगे 11 हजार वोल्ट के ट्रांसफॉर्मर के संपर्क में आ गया था। यह ट्रांसफॉर्मर बिना किसी घेराबंदी या सुरक्षा कवर के लगा हुआ था।

ट्रांसफॉर्मर की चपेट में आने और बिजली से जलने की वजह से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों को उसके दोनों हाथ कंधों के नीचे से काटने पड़े थे।

बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर पिता कोर्ट गए। उनकी ओर से मुआवजे की मांग की गई, लेकिन अक्टूबर 2005 में ट्रायल कोर्ट ने मुआवजे की मांग को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने उस समय इस घटना के लिए बच्चे की लापरवाही को ही जिम्मेदार ठहराया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए पीड़ित ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

मुआवजे ही नहीं केस लड़ने का पैसा भी दो

हाई कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया कि ट्रायल कोर्ट का पिछला फैसला सही नहीं था और उसने बिजली विभाग के अधिकारियों को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को निर्देश दिया कि वह 26।65 लाख रुपये का मुआवजा पीड़ित को दे। इसके साथ ही, 30 मई 1997 (जिस तारीख को केस दायर किया गया था) से लेकर मुआवजे की राशि मिलने तक, इस रकम पर 6 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज भी देने का आदेश दिया गया। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़ित को मुकदमेबाजी का खर्च भी दिया जाए, जिसमें ट्रायल और अपील के दौरान कोर्ट में जमा की गई फीस भी शामिल है। 15 अप्रैल को दिए अपने आदेश में, हाई कोर्ट ने बिजली बोर्ड को निर्देश दिया कि वह यह राशि एक महीने के भीतर जमा कराए। यदि बोर्ड ऐसा करने में नाकाम रहता है, तो याचिकाकर्ता के पास बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई (Execution Proceedings) शुरू करने का पूरा अधिकार होगा।

मदरसा में डिप्टी डायरेक्टर का औचक निरीक्षण

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। मछलीशहर स्थित मदरसा रियाजुल उलूम में डिप्टी डायरेक्टर विजय प्रताप यादव ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर कक्षा का जायजा लिया तथा व्यवस्थाओं की सराहना की। इस दौरान हाजी इमरान ने डिप्टी डायरेक्टर को स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर कक्षा की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में रुचि बढ़ी है और उनका शैक्षिक स्तर भी बेहतर हुआ है। डिप्टी डायरेक्टर ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए इसे सराहनीय बताया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कक्षा 1 की छात्रा आयत से आरेन्ज की स्पेलिंग पूछी, वहीं कक्षा 5 के छात्र साहेबे आलम से 'राष्ट्र गौरव कलाम' पाठ से संबंधित प्रश्न पूछे और पाठ पढ़वाया। दोनों छात्रों द्वारा सही उत्तर देने पर डिप्टी डायरेक्टर ने शिक्षकों और बच्चों की प्रशंसा की।उन्होंने मिड-डे मील (एमडीएम) भोजन, रसोई व्यवस्था, रजिस्टर, छात्रों की उपस्थिति, पठन-पाठन और साफ-सफाई का भी निरीक्षण किया, जिससे वे संतुष्ट नजर आए।इस अवसर पर प्रधानाचार्या महजबी बेगम, हाजी इमरान, रिजवान, फैजान, फरहत अंजुम, मोहम्मद वकील, नफीस अहमद, महमूद आलम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

पहले हीरो बनकर बचाया, फिर लड़की को हो गया प्यार ; शातिर जिम वाले की चाल में कैसे फंसी?

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के हरथला इलाके में एक जिम संचालक पर युवती के साथ शारीरिक शोषण करने और उसे ब्लैकमेल करने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता हरथला क्षेत्र की रहने वाली है। उसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले एक युवक उसका पीछा कर रहा था, जिससे वह काफी डरी हुई थी। इसी दौरान इलाके के एक जिम संचालक सुहैल मलिक ने हस्तक्षेप कर उसे उस युवक से छुटकारा दिलाया। इस घटना के बाद पीड़िता को सुहैल पर भरोसा हो गया और दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने हमदर्दी दिखाकर करीबियां बढ़ाईं और फिर उसे प्रेम संबंध में फंसा लिया। इसके बाद उसने शारीरिक संबंध बनाए और चोरी-छिपे उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। धीरे-धीरे आरोपी का व्यवहार बदल गया और उसने इन तस्वीरों व वीडियो का इस्तेमाल कर पीड़िता को धमकाना शुरू कर दिया।

वीडियो के दम पर ब्लैकमेलिंग और उगाही

शिकायत के अनुसार, आरोपी युवती को बदनाम करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल करता रहा। उसने डराकर उससे पैसों की मांग भी की और कथित तौर पर उगाही की। मानसिक दबाव और डर के कारण पीड़िता लंबे समय तक चुप रही, लेकिन जब स्थिति असहनीय हो गई तो उसने पुलिस का रुख किया।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

इस मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी जिम संचालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टीम आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।

पेंशनर्स 21 अप्रैल को करेगे धरना-प्रदर्शन

जौनपुर। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा केंद्र सरकार के पारित वित्त बिधेयक 2025 से पेंशनर्स के साथ सेवानिवृत्त की तिथि के अनुसार भेद-भाव करके, वेतन आयोग के टर्म्स रिफरेन्स से पेन्शनर्स को बाहर किए ,जाने के विरोध मे आगामी दिनांक-21अप्रैल को देश भर मे होने वाले बिरोध प्रदर्शन के साथ जनपद पर होने वाले बिरोध प्रदर्शन के तैयारी की समीक्षा बैठक जनपद अध्यक्ष सी बी सिंह की अध्यक्षता मे की गयी ।बैठक मे उपस्थित पेंशनर्स एवं पदाधिकारी अपने किए गए प्रयास से सदन को अवगत कराया ।जिला मंत्री कृपाशंकर उपाध्याय ने बताया कि संगठन के चलाए जा रहे पेंशनर्स हस्ताक्षर अभियान मे अबतक एक हजार आठ सौ पेंशनर्स हस्ताक्षर करके माननीय प्रधान मन्त्री भारत सरकार को भेजे जाने हेतु जमा किए है। पेंशनर्स के टर्म्स रिफरेन्स को आठवे बेतन आयोग मे सम्मिलित किए जाने तक हस्ताक्षर अभियान अनवरत चलता रहेगा।

'तूने मोबाइल चुराया...' शक में रिटायर्ड दारोगा के बेटे ने दोस्त के चेहरे पर बरसाए मुक्के, मौत

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां चोरी के शक में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. यह घटना हनुमान विहार थाना क्षेत्र की है. पुलिस घटना की जांच में जुटी है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी कपिल यादव को हिरासत में ले लिया गया.

जानकारी के अनुसार, मृतक सोनू अपने घर में परचून की दुकान चलाता था. उसका मोबाइल फोन अचानक गायब हो गया, जिसके बाद उसने अपने दोस्त कपिल यादव पर चोरी का शक जताया. कपिल, जो एक रिटायर्ड दरोगा का बेटा बताया जा रहा है, शुक्रवार दोपहर सोनू के घर आया था. दोनों ने साथ बैठकर शराब पी. इसी दौरान सोनू का मोबाइल फोन नहीं मिला तो उसने कपिल से इसके बारे में पूछताछ शुरू की.

कपिल ने मोबाइल अपने पास होने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन सोनू को उस पर शक था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई. विवाद इतना बढ़ गया कि सोनू ने कपिल की तलाशी लेने की कोशिश की. तलाशी लेने की इस कोशिश से कपिल गुस्से में आ गया और उसने सोनू पर हमला कर दिया.

आरोप है कि कपिल ने सोनू के चेहरे पर कई जोरदार मुक्के मारे, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया. गिरने के दौरान उसके सिर में गंभीर चोट आई और खून बहने लगा. शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल सोनू को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक की मां ने लगाए गंभीर आरोप

थाना प्रभारी राजीव सिंह के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. मृतक की मां माया देवी ने आरोप लगाया कि कपिल दबंग प्रवृत्ति का युवक है और वह अक्सर सोनू से जबरन शराब के पैसे मांगता था. उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार दोनों के बीच विवाद हो चुका था. वहीं, परिवार के लोगों ने बताया कि घटना वाले दिन ही सोनू की शादी की सालगिरह थी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है. इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि छोटे-छोटे विवाद किस तरह हिंसक रूप लेकर बड़ी घटनाओं में बदल जाते हैं.

हत्याकांड में तीनों आरोपी बरी, अधिवक्ता की पैरवी रही निर्णायक

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। जनपद के चर्चित एस.टी. नंबर 496/2013, धारा 302 भारतीय दंड विधान, थाना कुड़वार से जुड़े हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, कक्ष संख्या-1, संध्या चौधरी की अदालत ने रूपनारायण, दीप नारायण और राज नारायण तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

यह मामला राज्य बनाम रूपनारायण आदि के नाम से दर्ज था। घटना 3/4 दिसंबर 2012 की रात की बताई गई थी। वादी श्याम जी तिवारी (पुत्र रामकुमार तिवारी) द्वारा 4 दिसंबर 2012 को रात 11:10 बजे थाना कुड़वार में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि जमीनी विवाद के चलते नामजद आरोपियों ने वादी के भाई शिव उर्फ भोला तिवारी की हत्या कर दी और शव को उद्यान विभाग की अमरूद की बाग में पेड़ से हाथ बांधकर लटका दिया।

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाह पेश किए गए। वहीं, बचाव पक्ष ने भी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर मजबूती से अपनी दलीलें अदालत के समक्ष रखीं। इस पूरे मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुमार बाजपेई की प्रभावी और सशक्त पैरवी निर्णायक साबित हुई। उन्होंने गवाहों के बयान, साक्ष्यों की कमजोरियों और तथ्यों के विरोधाभास को अदालत के सामने मजबूती से रखा, जिसके चलते अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद आरोपियों और उनके परिजनों में राहत का माहौल है। वहीं, यह फैसला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।

स पर जूही, बर्रा, फीलखाना, काकादेव और गुजैनी थानों में करीब

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला बर्रा आठ की रहने वाली है और उस पर जूही, बर्रा, फीलखाना, काकादेव और गुजैनी थानों में करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं। गुजैनी थाना प्रभारी राजन शर्मा ने बताया कि इस मामले में बर्रा तीन स्थित जनता नगर निवासी भाजपा नेता आशीष प्रताप सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार उनके पिता रघुवीर सिंह ने काकादेव निवासी प्रॉपर्टी डीलर अमन सिंह के माध्यम से मेहरबान सिंह का पुरवा में 22 लाख रुपये में एक प्लॉट खरीदा था। बाद में जब प्लॉट को बेचने की कोशिश की गई तो सामने आया कि उसी जमीन की कई बार फर्जी रजिस्ट्रियां कर दी गई थीं।

अमन सिंह के गिरोह में शामिल विभा सचान और अजय पटेल ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। जब पीड़ित पक्ष ने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उन्हें धमकाया। इस घटनाक्रम के चलते सदमे में आकर रघुवीर सिंह की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक, यह कोई पहला मामला नहीं था। बीते साल फरवरी में भी कई लोगों—राजीव सचान, जयपाल यादव, सुनील सिंह, योगेश सचान, ओपी यादव, सुधीर यादव, सुदेश चंद्र और प्रशांत मिश्रा—ने विभा सचान, उसके पति बाबू सचान और अजय पटेल समेत अन्य के खिलाफ फर्जी रजिस्ट्री के जरिए ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

जांच के दौरान पुलिस ने गिरोह के अन्य सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन विभा सचान लगातार फरार चल रही थी। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। थाना प्रभारी के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने रामगोपाल चौराहा से आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब गिरोह के अन्य संभावित नेटवर्क और ठगी के मामलों की जांच में जुटी है।

स्कूल जाने निकला छात्र लापता, परिजनों में दहशत

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। केराकत कोतवाली क्षेत्र के विक्रमपुर गांव से एक 16 वर्षीय छात्र के लापता होने का मामला सामने आया है। छात्र के घर वापस न लौटने पर परिजनों में दहशत व्याप्त हो गया। काफी खोजबीन के बाद जब उसका कोई पता नहीं चला तो पिता ने केराकत कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विक्रमपुर गांव निवासी रामधनी कुमार पुत्र बब्बर राम का 16 वर्षीय पुत्र राजवीर कुमार बुधवार की सुबह लगभग 8 बजे घर से पसेवा गांव स्थित मां वैष्णो इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए निकला था। लेकिन शाम तक जब वह घर वापस नहीं पहुंचा तो परिवार के लोगों की चिंता बढ़ गई। परिजनों ने पहले अपने स्तर से रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में काफी तलाश की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला।इसके बाद परिजन विद्यालय पहुंचे और वहां जानकारी ली। विद्यालय प्रशासन ने बताया कि राजवीर उस दिन स्कूल आया ही नहीं था। यह सुनते ही परिजनों के होश उड़ गए। परेशान पिता ने तत्काल केराकत कोतवाली पहुंचकर अपने बेटे के लापता होने की सूचना पुलिस को दी और जल्द खोजबीन की मांग की।राजवीर के पिता ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि उनका बेटा सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। बेटे के अचानक लापता होने से परिवार के सभी सदस्य बेहद चिंतित हैं। पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर मामले की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद गांव और आस-पास के क्षेत्र में भी चिंता का माहौल है।

इटावा की सैय्यद बाबा मजार अवैध घोषित, वन विभाग की जमीन पर निर्माण, कब्जा हटाने के आदेश जारी

आर्यावर्त संवाददाता

इटावा। यूपी के इटावा के बीहड़ इलाके में स्थित सैय्यद बाबा मजार को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। वन विभाग की कोर्ट ने इस मजार को आरक्षित वन भूमि पर अवैध कब्जा मानते हुए इसे हटाने के आदेश दिए हैं। पक्षकार की ओर से मजार को लेकर कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं पेश करने के बाद वन विभाग की कोर्ट ने यह आदेश जारी किया।

करीब दो महीने तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने यह स्पष्ट किया कि जिस जमीन पर मजार बनी है। वह लंबे समय से वन विभाग के रिकॉर्ड में आरक्षित श्रेणी में दर्ज है। ऐसे में वहां किसी भी तरह की स्थायी संरचना या धार्मिक गतिविधि बिना अनुमति के गैरकानूनी मानी जाएगी।

मजार से जुड़े पक्षकारों का दावा था कि यह स्थल करीब 800 साल पुराना है और यहां हर साल उर्स का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं, लेकिन अदालत में इस दावे के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज या ऐतिहासिक प्रमाण पेश नहीं किया जा सका। जिसके बाद कोर्ट ने इसे हटाने का आदेश जारी किया।

सरकारी रिकॉर्ड बना आधार

अदालत ने अपने फैसले में 1916, 1939 और 1946 के सरकारी गजट का हवाला दिया, जिनमें इस जमीन को आरक्षित वन क्षेत्र बताया गया है। लगभग 1800 वर्गफीट क्षेत्र में फैले इस ढांचे को नियमों के खिलाफ मानते हुए अवैध घोषित कर दिया गया।

कई मौके, फिर भी नहीं मिले सबूत

मजार के पक्षकारों को पांच बार अलग-अलग तारीखों पर अपने पक्ष में दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया, लेकिन हर बार वह कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं करा सके। इसके बाद अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में एकतरफा नहीं, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर फैसला सुनाया।

क्या है पूरा मामला?

इस पूरे विवाद की शुरुआत इस साल जनवरी में हुई, जब वन विभाग के रेंजर ने इस निर्माण को अवैध बताते हुए मामला दर्ज कराया। फरवरी से सुनवाई शुरू हुई और मार्च के अंत तक पक्षकारों को समय दिया गया, लेकिन कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। अंततः 17 अप्रैल को अदालत ने अपना निर्णय सुना दिया।

अब आगे क्या?

वन विभाग ने साफ किया है कि आदेश के खिलाफ अपील का विकल्प खुला है। फिलहाल मजार हटाने की तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन विभाग ने संकेत दिया है कि आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी।

नाला सफाई अभियान शुरू, बरसात से पहले जलभराव रोकने की तैयारी

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। नगर पालिका परिषद ने आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए शहर में व्यापक सफाई अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान का शुभारंभ पालिकाध्यक्ष प्रवीण कुमार अग्रवाल ने करौंदिया नाले की सफाई कार्य को हरी झंडी दिखाकर किया।

नगर क्षेत्र के करीब 30 बड़े और मझोले नालों के साथ-साथ सभी वार्डों की नालियों की तल्लीझार सफाई कराई जाएगी। पालिकाध्यक्ष ने बताया कि बरसात के दौरान जलभराव और जल निकासी की समस्या से संक्रामक रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही आम लोगों को आवागमन में भी दिक्कत होती है। इन समस्याओं से पहले ही निपटने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। सफाई कार्य को तेज़ी से पूरा करने के लिए जेसीबी और नाला मैन मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा झारखंड से 50 प्रशिक्षित श्रमिकों को भी बुलाया गया है, ताकि बारिश शुरू होने से पहले सभी नालों की सफाई पूरी हो सके।

वहीं संकरी गलियों में कूड़ा उठान की समस्या को देखते हुए सभी वार्डों में सफाई कर्मचारियों को नई हत्थू ठेला गाड़ियां भी वितरित की गई हैं, जिससे डोर-टू-डोर कलेक्शन व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। पालिकाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नालों की गहराई तक सफाई कराई जाए और निकाले गए सिल्ट को तुरंत हटाकर उसका निस्तारण किया जाए, ताकि वह दोबारा नालियों में न जाए। साथ ही उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि नालों पर किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटा लें, अन्यथा सफाई अभियान के दौरान कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर कई सभासद, पालिका

हर टाइम ज्यादा सोचना, जापानी तरीके हैं ओवरथिंकिंग का बेस्ट इलाज

ओवरथिंग एक ऐसी समस्या है जो मेंटल हेल्थ को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। आजकल अमूमन लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ जापानी तरीके ऐसे हैं, जो ओवरथिंग को कम करने में मदद करते हैं। चलिए जानते हैं उनके बारे में।

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दिमाग भी कभी रुकता नहीं है। एक काम खत्म होता नहीं कि दूसरे कि चिंता रहता है। ऐसे में ओवरथिंग की समस्या अब अमूमन लोगों को होने लगी है। मन में किसी न किसी चीज को लेकर कुछ न कुछ सोचना आम बात हो गई है। ये एक ऐसी प्रॉबल्म है जो आपकी मेंटल हेल्थ को काफी खराब कर सकती है। छोटी-छोटी बातें दिमाग घूमना, बीती हुई गलतियों का पछतावा और आने वाले समय की चिंता मिलकर इंसान को थका देती है। कई बार तो हम किसी समस्या का हल निकालने के बजाय उसी के बारे में बार-बार सोचकर उसे और बड़ा बना देते हैं। यही वजह है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिक स्थिति बन जाती है जो आत्मविश्वास, नींद और खुशियों पर गहरा असर डालती है।

लोगों को लगता है कि ओवरथिंग को कम नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जापान जैसे देश, जहां लोग सादगी, संतुलन और मानसिक शांति को जीवन का हिस्सा मानते हैं। वहां से हमें कई ऐसे तरीके मिलते हैं जो ओवरथिंकिंग को कम करने में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। अगर आप भी ओवरथिंग का शिकार हैं तो ये जापानी तरीके आपको राहत पहुचांने में काफी मदद करेंगे। चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं उनके बारे में।

जीने की छोटी सी वजह

ओवरथिंग को कम करने का ये एक छोटा सा तरीका है। इसका मतलब होता है जीने के छोटी सी वजह। जैसे कोई काम, कोई शौक या कोई इंसान जिसके साथ आपको खुशी मिलती है। इसमें आपको रोज सुबह उठकर खुद से ये सवाल करना है कि आज ऐसा क्या करूं जिससे मुझे खुशी मिलेगी। फिर दिन में 1-2 काम ऐसे करें जिनसे आपका दिल खुश हो। छोटी-छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना शुरू कर दें। यह आपको बेकार की सोच से हटाकर काम पर ध्यान लगाने में मदद करता है।

अधूरेपन में भी खूबसूरती

ये समझाता है कि हर कुछ परफेक्ट नहीं होता है। कभी थोड़ा कम ज्यादा भी होना भी लाइफ का हिस्सा है। इसमें आप अपनी हर गलती को सीख की तरह लें न कि फेल होने की तरह। घर या काम में परफेक्शन के पीछे भागना कम करें। साथ ही खुद से कहें कि जैसा है, बस ठीक है। ऐसा करने से आप अपनी गलतियों पर ज्यादा सोचना छोड़ देते हैं। जिससे ओवरथिंग कम होती है।

प्रकृति के साथ समय

अगर आप ओवरथिंग करते हैं तो आपको नेचर के बीच कुछ देर समय बिताना चाहिए। जापान में इस तरीके को Shinrin-yoku कहा जाता है। इसमें पेड़-पौधों और खुले माहौल में समय बिताना होता है। आप रोज 10 से 15 मिनट पार्क या किसी गार्डन में वॉक करें। इस दौरान फोन का इस्तेमाल न करें। बल्कि प्रकृति से बातें करें। पक्षियों की आवाज और हवा को महसूस करें। इससे दिमाग शांत होता है और फालतू विचार कम होते हैं।

टूटने के बाद भी खुद को मजबूत बनाना

गलतियां और मुश्किलें आपको कमजोर नहीं बनातीं, बल्कि मजबूत बनाती हैं। Kintsugi हमे यही सिखाता है। इसलिए अपनी किसी पुरानी गलती को लिखें और सोचें आपने उससे क्या सीखा। खुद को बार-बार दोष देना बंद करें। साथ ही ये याद रखें कि हर इंसान कभी न कभी टूटता है। ऐसा करने से आप अपनी पुरानी गलतियों में उलझना छोड़ देते हैं।

बस जितना जरूरी हो उतना

जब लगे कि दिमाग ज्यादा सोच रहा है, तो खुद को वहीं रोकें और खुद से कहें, मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। इसके अलावा सोशल मीडिया और फोन का समय लिमिट करें। यानी कुल मिलाकर कहें तो हर चीज में लिमिट रखें। चाहे फिर वो खाने में हो या फिर सोचने में। ये आदात भी ओवरथिंग को कम करने में काफी हद तक मदद करती है।

हर किसी का अपना समय

कुछ लोग खुद को दूसरे से कम्पेयर करते रहते थे। जो ओवरथिंग का सबसे बड़ा कारण है। ऐसे में आपको Oubaitori फॉलो करना चाहिए। जो हमे ये सिखाता है कि हर इंसान अपनी स्पीड से आगे बढ़ता है। ऐसे में तुलना करने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ से खुद को कम्पेयर करना कम करें। अपने छोटे-छोटे प्रोग्रेस पर ध्यान दें और खुद से कहेंगे की 'मेरा टाइम भी आएगा'।

कानों से जुड़ी इन 5 गलत धारणाओं को सच मानते हैं लोग

कान हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा हैं और इनकी देखभाल करना बहुत अहम है। हालांकि, कानों से जुड़ी कई गलत धारणाएं हैं, जिन्हें लोग सच मानकर अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा लेते हैं। इन गलत धारणाओं में से कुछ तो इतनी आम हैं कि लोग इन्हें बार-बार सुनते हैं और बिना सोचे-समझे अपनाते भी हैं। आइए आज हम आपको कानों से जुड़ी ऐसी ही कुछ गलत धारणाओं और उनकी सच्चाई के बारे में बताते हैं।

क्या कानों में झांकना खतरनाक होता है?

कई लोगों का मानना है कि किसी के कान में झांकना खतरनाक हो सकता है। हालांकि, सच्चाई यह है कि अगर कान साफ हो और कान के पर्दे पर जोर से न झांका जाए तो कान में झांकने से कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा कानों में झांकने से कान की गहराई तक पहुंचना मुश्किल होता है, इसलिए कानों में झांकने से कोई नुकसान नहीं होता।

क्या कान में रूई लगाना जरूरी होता है?

अक्सर लोग यह मानते हैं कि कान में रूई लगाना जरूरी होता है, खासकर जब बारिश हो या तैराकी के बाद। हालांकि, ऐसा करना गलत है क्योंकि इससे कान में नमी फंस सकती है और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। बेहतर होगा कि बारिश के बाद या तैराकी के बाद कान को अच्छे से पोंछ लें ताकि नमी न रहे और संक्रमण का खतरा भी कम हो जाए।

क्या कान में मोम होना बुरा संकेत है?

यह भी एक आम धारणा है कि कान में मोम होना बुरा संकेत है। असल में कान में मोम होना एक सामान्य प्रक्रिया है और यह कान को संक्रमण से बचाने में मदद करता है। अगर मोम बहुत अधिक हो या गाढ़ा हो तो डॉक्टर से जांच कराएं ताकि कोई समस्या न हो। अपने कान को साफ रखने के लिए कभी भी किसी भी तरह के घरेलू उपाय अपनाने की बजाय डॉक्टर की सलाह लें।

क्या कान में दर्द होना हमेशा संक्रमण का संकेत होता है?

यह भी एक आम धारणा है कि कान में दर्द होना हमेशा संक्रमण का संकेत होता है। असल में कान में दर्द कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि दांतों की समस्या, साइनस संक्रमण या हवा के दबाव में बदलाव। इसलिए जब भी आपके कान में दर्द हो तो डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सही कारण पता चल सके और उचित इलाज मिल सके। सही जानकारी और समय पर इलाज लेने से समस्या जल्दी ठीक हो सकती है।

क्या कान में हेयरपिन डालने से कान में मोम निकलता है?

यह भी एक आम धारणा है कि कान में हेयरपिन डालने से कान में मोम निकलता है। हालांकि, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे कान के पर्दे को नुकसान पहुंच सकता है या कान की गहराई तक पहुंच कर चोट लग सकती है। इसलिए कभी भी इस तरह के घरेलू उपाय अपनाने की बजाय डॉक्टर की सलाह लें और कान की सफाई के लिए सुरक्षित तरीके अपनाएं।

कर्ली हेयर से जुड़े वो मिथक, जिनपर आसानी से भरोसा कर लेते हैं लोग

कर्ली हेयर को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में लोग सुनी-सुनाई बातों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। अगर आपके बाल भी कर्ली हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए है। यहां हम आपको कर्ली हेयर से जुड़े 5 मिथक के बारे में बताने जा रहे हैं।

कर्ली हेयर यानी घुंघराले बाल काफी कम ही लोगों के देखने को मिलते हैं। इस तरह के बालों को लोग काफी पसंद करते हैं, क्योंकि ये दिखने में काफी बाउंसी और अट्रैक्टिव होते हैं। इनकी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए अलग तरीके से देखभाल की भी जरूरत होती है। लेकिन कर्ली हेयर को लेकर कई तरह के मिथक भी सुनने को मिलते हैं, जिनपर लोग आसानी से भरोसा भी कर लेते हैं। अक्सर यह माना जाता है कि कर्ली बाल संभालना बहुत मुश्किल होता है, ये हमेशा रूखे और उलझे रहते हैं या फिर इन्हें बार-बार धोना और स्ट्रेट करना ही सही तरीका है। सोशल मीडिया, अधूरी जानकारी और सुनी-सुनाई बातों के कारण ये धारणाएं और भी मजबूत हो जाती हैं, जिससे लोग अपने बालों की सही देखभाल नहीं कर पाते।

लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कर्ली हेयर की जरूरत को सही से समझते हैं तो उन्हें खूबसूरत और मैनेजेबल बनाना काफी आसान हो सकता है। अगर आपके बाल भी कर्ली हैं और उनकी देखभाल को लेकर आपको कोई कंफ्यूज या फिर मिथ लेकर बैठी हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए है। चलिए आपको बताते हैं कर्ली हेयर से जुड़े 5 मिथक और उनकी सच्चाई के बारे में।

1- मिथक: कर्ली बाल हमेशा रूखे और बेजान होते हैं

सच्चाईः कर्ली बाल नेचुरली ड्राई हो सकते हैं क्योंकि स्कैल्प का ऑयल पूरी लंबाई तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे हमेशा बेजान ही रहें। सही मॉइस्चर, कंडीशनिंग और हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स से कर्ली बाल भी सॉफ्ट, शाइनी और हेल्दी दिख सकते हैं।

2- मिथकः कर्ली हेयर को रोज धोना चाहिए

सच्चाईः बार-बार बाल धोने से कर्ली हेयर और ज्यादा ड्राई हो सकते हैं। कर्ली बालों को हफ्ते में 2 से 3 बार धोना ही बेहतर होता है, ताकि उनकी नेचुरल नमी बनी रहे और फ्रिज़ कम हो।

3- मिथक: कर्ली बालों को कंघी नहीं करनी चाहिए

सच्चाईः कर्ली बालों को सूखे में कंघी करने से फ्रिज़ बढ़ता है, इसलिए यह मिथक आधा सच है। सही तरीका है कि गीले या हल्के गीले बालों में वाइड-टूथ कंघी से धीरे-धीरे सुलझाएं, जिससे बाल टूटें नहीं और कर्ल्स भी डिफाइन रहें।

4- मिथक: कर्ली हेयर हमेशा उलझे रहते हैं

सच्चाईः अगर सही केयर न हो तो उलझ सकते हैं, लेकिन सही रूटीन। जैसे लीव-इन कंडीशनर, ऑयलिंग और प्रोटेक्टिव स्टाइल से कर्ली बाल आसानी से मैनेज हो सकते हैं और उलझने की समस्या काफी कम हो जाती है।

5- मिथक: कर्ली बालों को स्ट्रेट करना ही बेहतर होता है

सच्चाईः बार-बार हीट स्टाइलिंग से कर्ली बाल डैमेज हो सकते हैं और उनका नेचुरल पैटर्न खराब हो जाता है। आजकल ट्रेंड यही है कि अपने नेचुरल कर्ल्स को अपनाया जाए और उन्हें सही तरीके से स्टाइल किया जाए, ताकि बाल हेल्दी और खूबसूरत बने रहें।

किशमिश या मुनक्का...गर्मियों में क्या खाना है ज्यादा फायदेमंद?

गर्मियों का मौसम आते ही खानपान में भी बदलान शुरु हो जाता है। इस मौसम में शरीर को ज्यादा ठंडक की जरूरत होती है। ऐसे में लोग अपनी डाइट में गर्म चीजों को हटाकर ठंडी चीजों को शामिल करते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या गर्मियों में किशमिश या मुनक्का खाना चाहिए। दोनों ही अंगूर से बने होते हैं और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन इनकी तासीर, असर और शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव अलग-अलग होते हैं, जिसकी वजह से सही चुनाव करना जरूरी हो जाता है।

कई लोग बिना जानकारी के कभी भी किसी भी समय इन्हें खाना शुरू कर देते हैं। जबकि मौसम के हिसाब से सही चीज चुनना ज्यादा जरूरी होता है। खासकर गर्मियों में ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जो शरीर को ठंडक दे, पाचन को हल्का रखे और डिहाइड्रेशन से बचाए। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किशमिश या मुनक्का में से किसे चुनें तो ये आर्टिकल आपके लिए है। चलिए बताते हैं दोनों के बीच क्या है ज्यादा बेहतर।

किशमिश और मुनक्का...कौन है पोषक तत्व में आगे?

किशमिश और मुनक्का दोनों ही अंगूर से बनाए जाते हैं। लेकिन दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए ज्यादा पोषक तत्वों की, तो मुनक्का थोड़ा आगे माना जाता है। मुनक्का आकार में बड़ा और कम प्रोसेस्ड होता है, जिसमें आयरन, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। जो शरीर की कमजोरी दूर करने, खून बढ़ाने और इम्युनिटी मजबूत करने में मदद करते हैं। वहीं किशमिश में भी फाइबर, नेचुरल शुगर और एनर्जी भरपूर होती है, जो तुरंत ताकत देने और पाचन को बेहतर बनाने में सहायक है। दोनों की ही तासीर गर्म होती है। लेकिन किशमिश को भिगोने पर अपनी तासीर बैलेंस कर लेती है।

किशमिश और मुनक्के के फायदे

किशमिश और मुनक्के दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन इनके फायदे थोड़ा अलग होते हैं। किशमिश हल्की होती है और जल्दी एनर्जी देने का काम करती है, साथ ही यह पाचन को बेहतर बनाकर कब्ज की समस्या को कम करने में मदद करती है और शरीर को ठंडक भी देती है, इसलिए गर्मियों में ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। वहीं मुनक्का ज्यादा पौष्टिक और ताकतवर माना जाता है, जो खून बढ़ाने, कमजोरी दूर करने और इम्युनिटी मजबूत करने में मदद करता है। इसके अलावा मुनक्का गले की खराश और सूखी खांसी में भी राहत देता है।

गर्मियों में क्या खाना है बेहतर?

आयुर्वेद एक्सपर्ट किरण गुप्ता बताती हैं कि वैसे तो दोनों ही काफी ताकतवर सूखे मेवे हैं। लेकिन गर्मियों में अगर डाइट में किसी एक को शामिल करने की बात आए तो किशमिश थोड़ी ज्यादा बेहतर है। इसे आप भिगोकर खा सकते हैं। मुनक्का ताकत ज्यादा देता है। लेकिन इसकी तासीर ज्यादा गर्म होती है। हालांकि, आप इसे तवे पर हल्का सा सेंक कर कम मात्रा में खा सकते हैं।

किस जाति के लोग देते हैं कितना टैक्स, क्या इसकी भी आएगी रिपोर्ट?

जातिगत जनगणना के साथ करदाताओं का डेटा भी सार्वजनिक करने की मांग उठी है। CTI का कहना है कि इससे पता चलेगा किस वर्ग का अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है और उसी आधार पर नीतियां बननी चाहिए।

जातिगत जनगणना की घोषणा के बाद अब करदाताओं के डेटा को लेकर नई बहस छिड़ गई है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने मांग की है कि सरकार यह भी बताए कि किस जाति के लोग कितना टैक्स देते हैं, ताकि आर्थिक योगदान के आधार पर नीतियां बन सकें। देश में 14 साल बाद शुरू होने जा रही जनगणना प्रक्रिया और जातिगत जनगणना की घोषणा के बाद अब एक नई मांग सामने आई है। दिल्ली और देश के प्रमुख व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने सरकार से अपील की है कि जातिगत आंकड़ों के साथ-साथ करदाताओं का भी विस्तृत डेटा सार्वजनिक किया जाए। हालांकि, यह अभी सिर्फ मांग ही की गई है। इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है।

CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि जब सरकार जाति आधारित सर्वे कर रही है, तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि किस जाति के लोग कितना टैक्स देते हैं। उनका तर्क है कि इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में किन वर्गों की कितनी भूमिका है।

गोयल के मुताबिक, सरकार के पास इनकम टैक्स और जीएसटी से जुड़ा पूरा डेटा पहले से मौजूद है, लेकिन इसे जाति के आधार पर कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। CTI का मानना है कि अगर यह जानकारी सामने आती है, तो नीति निर्माण अधिक संतुलित और पारदर्शी हो सकता है।

क्या हुई है मांग?

CTI वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग और उपाध्यक्ष राहुल अदलखा का कहना है कि आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन-सी जाति सरकार को कितना राजस्व देती है। ऐसे में, जो वर्ग सबसे अधिक टैक्स देता है, उसके लिए विशेष नीतियां, बीमा, पेंशन और मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए।

वहीं, CTI महासचिव गुरमीत अरोड़ा और रमेश आहूजा ने कहा कि देश में करीब 6 करोड़ व्यापारी हैं, जबकि दिल्ली में ही 20 लाख व्यापारी सक्रिय हैं। इन करदाताओं को भी सामाजिक समानता के तहत उनका उचित अधिकार मिलना चाहिए। CTI की इस मांग को लेकर ट्रेडर्स कम्युनिटी में जोरदार चर्चा हो रही है और बड़ी संख्या में व्यापारियों ने इसका समर्थन भी किया है।

एलपीजी और कच्चे तेल पर सरकार का बड़ा अपडेट, देश में एलपीजी और कच्चे तेल की कोई कमी नहीं

देश में एलपीजी और कच्चे तेल की उपलब्धता को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि किसी भी तरह की कमी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में पर्याप्त कच्चे तेल का भंडार मौजूद है और घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

सरकार के मुताबिक, देशभर में एलपीजी वितरण पूरी तरह सुचारु है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर स्तर पर कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हाल ही में एक दिन में करीब 50 लाख सिलेंडर की बुकिंग दर्ज की गई, जबकि डिलीवरी दर लगभग 93% रही। उन्होंने बताया कि 98% बुकिंग अब ऑनलाइन हो रही है, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनी है। हालांकि, गर्मी के मौसम की वजह से बुकिंग में हल्की गिरावट आई है और यह आंकड़ा अब करीब 45-46 लाख सिलेंडर तक आ गया है।

नए कनेक्शन और सख्त कार्रवाई

मार्च 2026 से अब तक करीब 4.68 लाख नए PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा, नियमों का उल्लंघन करने वाले 255 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर जुर्माना लगाया गया है, जबकि 55 को निलंबित किया गया है। 23 मार्च के बाद से अब तक 16.5 लाख से ज्यादा छोटे (5 किलो) सिलेंडर भी बेचे जा चुके हैं।

बंदरगाह और सप्लाई चेन पर अपडेट

शिपिंग मंत्रालय की ओर से मुकेश मंगल ने बताया कि देश के सभी बंदरगाह सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और कहीं भी भीड़भाड़ की स्थिति नहीं है। इससे सप्लाई चेन पर कोई असर नहीं पड़ा है।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और यात्रियों की स्थिति

विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव असीम आर महाजन ने जानकारी दी कि 28 फरवरी से अब तक करीब 10.38 लाख यात्री भारत लौट चुके हैं। उन्होंने बताया कि यूएई से भारत के लिए करीब 100 उड़ानें संचालित होने की उम्मीद है। वहीं सऊदी अरब, ओमान और कुवैत से भी नियमित उड़ानें जारी हैं। कतर का हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खुला है, जहां से सीमित उड़ानें चल रही हैं। बहरीन से भी जल्द सीमित फ्लाइट्स शुरू होने की योजना है।

कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में

सरकार का कहना है कि एलपीजी, कच्चे तेल, बंदरगाह संचालन और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

आरबीआई में निकली जूनियर इंजीनियर की भर्ती, 11 पदों के लिए आवेदन शुरू

नई दिल्ली, एजेंसी। देश का एकमात्र केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में नौकरी करने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने जूनियर इंजीनियर (जेई) के विभिन्न 11 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। आरबीआई ने जेई के जिन 11 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, उनमें जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 7 और जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के 4 पद शामिल हैं। आरबीआई की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया गुरुवार, 16 अप्रैल से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 6 मई निर्धारित की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय लास्ट डेट तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय या बोर्ड से संबंधित इंजीनियरिंग विषय में न्यूनतम 65त्न अंकों के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता और तय सालों का अनुभव होना भी अनिवार्य है।

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसकी गणना 1 अप्रैल के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन परीक्षा, भाषा प्रवीणता परीक्षा (एलपीटी), मेडिकल परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की शुरुआती सैलरी 47,700 से 91,309 रुपए के बीच प्रति माह होगी। इसी के साथ कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जो सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपए के साथ 18त्न जीएसटी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग/अतिरिक्त श्रेणी के लिए 50 रुपए के साथ 18त्न जीएसटी तय किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद के लिए दिए गए सक्रिय आवेदन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान कर फॉर्म को सबमिट कर दें। लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित निकालकर रख लें।

डील नहीं हुई तो ईरान पर फिर होगी बमबारी... ट्रंप का अल्टीमेटम

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के साथ बुधवार तक समझौता नहीं हुआ, तो अमेरिका फिर से बमबारी शुरू कर सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सीजफायर को बढ़ाया भी जा सकता है और खत्म भी किया जा सकता है। ट्रंप ने यह बात एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कही, जब वह फीनिक्स से वॉशिंगटन लौट रहे थे। अमेरिका-ईरान के बीच 8 अप्रैल को 2 हफ्ते का सीजफायर हुआ था, जो 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है।

ट्रंप ने कहा, हो सकता है मैं सीजफायर आगे न बढ़ाऊं, लेकिन ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी जारी रहेगी। ऐसे में हमें फिर से बम गिराने पड़ सकते हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत रुकी हुई है। हाल ही में पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत हुई थी, लेकिन उससे कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।

दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। इनमें आर्थिक प्रतिबंध हटाने का सवाल, ईरान का परमाणु कार्यक्रम और समुद्री सुरक्षा शामिल हैं। इन वजहों से समझौते की राह मुश्किल हो गई है। इस विवाद में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका का कहना है कि यह रास्ता सुरक्षित और खुला है, लेकिन ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर दबाव बढ़ता रहा, तो वह इस रास्ते को बंद या सीमित कर सकता है। अमेरिका का कहना है कि उसने ईरान के बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी कर रखी है, ताकि जहाजों की आवाजाही रोकी जा सके। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, कई जहाजों को वापस लौटा दिया गया है। वहीं ईरान इस कदम को गैरकानूनी और उकसाने वाला बता रहा है। वहीं ईरान के नेताओं का कहना है कि अगर यह नाकेबंदी जारी रही, तो इसका असर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर भी पड़ेगा, जिससे दुनिया भर के बाजार प्रभावित हो सकते हैं।

शेख हसीना बांग्लादेश को सौंप दी जाएंगी? क्या सोच रही सरकार, विदेश मंत्रालय ने बताया

ढाका, एजेंसी। भारत सरकार ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर ढाका की औपचारिक मांग की समीक्षा शुरू कर दी है। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने (MEA) ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी और न्यायिक ढांचे के तहत आगे बढ़ रही है। 2024 में बांग्लादेश में हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हसीना की सरकार गिर गई थी, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और भारत आ गई थीं, तभी से वो भारत में रह रही हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि प्रत्यर्पण अनुरोध का गहन परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मामला न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं के तहत विचाराधीन है। हम सभी पक्षों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे और घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए हैं।

जायसवाल ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब भारत जुलाई क्रांति के नाटकीय राजनीतिक परिवर्तनों के बाद ढाका में नवगठित सरकार के साथ अपनी साझेदारी को स्थिर करने का प्रयास कर रहा है। भारत बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को स्थिर और मजबूत बनाए रखने की दिशा में काम कर रहा है।

कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जांच की जा रही

रणधीर जायसवाल ने कहा, 'शेख हसीना के प्रत्यर्पण के संबंध में एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसकी हमारी न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जांच की जा रही है। भारत बांग्लादेश के साथ संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। जल्द ही दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर आधिकारिक चर्चा होने की भी उम्मीद है।

2024 से भारत में हैं शेख हसीना

भारत ने 2025 में प्रत्यर्पण अनुरोध प्राप्त करने की बात स्वीकार की थी, लेकिन अब भारत की न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत इसकी गहन समीक्षा की जा रही है।रिपोर्ट के अनुसार, जायसवाल ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रक्रिया आंतरिक कानूनी प्रोटोकॉल के अधीन है। अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद से हसीना भारत में ही हैं और उनकी उपस्थिति को लेकर संवेदनशीलता बनी हुई है इसके बावजूद नई दिल्ली नए प्रशासन के प्रति "सामान्य कामकाज" का रुख अपना रही है।

'द्विपक्षीय रिश्तों को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा'

इसके आगे जयसवाल ने दोनों देशों के बीच चल रही राजनयिक गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कहा 'मैं यह भी दोहराना चाहूंगा कि विदेश मंत्री ने नई सरकार के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत करने और अमेरिकी मूल्यों को और मजबूत करने की भारत की इच्छा को दोहराया। दोनों पक्ष संबंधित द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से साझेदारी को गहरा करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सहमत हुए। पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दोनों पक्षों के विचारों के लिए जल्द ही आधिकारिक बैठकें होने की उम्मीद है'। MEA ने साफ संकेत दिया है कि नई सरकार के साथ संबंध सामान्य रूप से जारी रहेंगे और किसी एक व्यक्ति के मुद्दे से द्विपक्षीय रिश्तों को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।

अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत, फाइनल हुआ इस्लामाबाद में वार्ता का दिन!

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर समझौते के बाद एक बार फिर से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। खबर है कि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताहांत पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार (20 अप्रैल) को इस्लामाबाद में अहम वार्ता होने की संभावना है। हालांकि, अमेरिका ने अभी तक इन वार्ताओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आए हैं जब पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए नए राजनयिक प्रयास चल रहे हैं। तुर्की में आयोजित अंताल्या कूटनीति मंच (Antalya Diplomacy Forum) के दौरान प्रमुख क्षेत्रीय नेताओं ने तनाव कम करने पर केंद्रित वार्ता की। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस बैठक में क्षेत्रीय तनाव कम करने और राजनयिक समाधानों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों पर चर्चा हुई।रिपोर्ट के मुताबिक कतर के अमीरी दीवान ने कहा 'अमीर और तुर्की के राष्ट्रपति ने इस संबंध में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और प्रधानमंत्री के प्रयासों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया'।

पाक सेना प्रमुख ने ईरानी संसद के अध्यक्ष से की मुलाकात

इस बीच अमेरिका-ईरान वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए राजनयिक प्रयास तेज होने के मद्देनजर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने गुरुवार (16 अप्रैल) को तेहरान में ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ से मुलाकात की। मुनीर का यह दौरा अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में आई तेजी के बीच हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी अधिकारियों ने विशेष रूप से तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर किसी बड़ी सफलता की उम्मीद जताई है। बुधवार को तेहरान पहुंचे मुनीर का स्वागत ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने किया। इस यात्रा का मकसद पहले दौर की वार्ता के असफल रहने के बाद संभावित दूसरे दौर की वार्ता के लिए जमीन तैयार करना है।

पहले हुई वार्ता रही असफल

दरअसल बीते 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता में अमेरिका और ईरान के बीच 39 दिनों से चल रहे तनाव को खत्म करने की कोशिश की गई थी।हालांकि यह बातचीत किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी।पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई ये वार्ता, 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच पहली उच्च स्तरीय आमने-सामने की वार्ता थी।

इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्धविराम

इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच 10 दिनों के युद्धविराम की घोषणा की, जिसे व्यापक तनाव कम करने की दिशा में एक संभावित कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह युद्धविराम इजराइल-लेबनान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच हुआ है, जहां इजराइली सशस्त्र बलों और हिजबुल्लाह के बीच झड़पें हुई हैं, जो इस क्षेत्र में अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद काफी बढ़ गई हैं। इससे पहले गुरुवार को ट्रंप ने घोषणा की कि इस क्षेत्र में शत्रुता को कम करने के लिए गहन राजनयिक प्रयासों के बाद इजराइल और लेबनान 10 दिनों के युद्ध विराम की शुरुआत करने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि उन्होंने लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ औन और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत की और पुष्टि की कि दोनों नेताओं ने एक व्यापक समाधान की दिशा में एक कदम के रूप में अस्थायी युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्धता जताई है। यह युद्धविराम पश्चिम एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हुआ है, क्योंकि इससे पहले इजराइल-लेबनान सीमा पर काफी अस्थिरता का दौर चल रहा था।

ऑस्ट्रेलिया को 58,500 करोड़ के 11 युद्धपोत देगा जापान, चीन के खिलाफ बड़ा रक्षा समझौता

सिडनी, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया और जापान ने शनिवार को एक बड़े रक्षा समझौते पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। यह करीब 10 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 7 अरब अमेरिकी डॉलर) का युद्धपोत सौदा है। 2014 में जापान द्वारा सैन्य निर्यात पर लगी पाबंदी हटाने के बाद यह उसका सबसे बड़ा रक्षा सौदा माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने कहा कि वे इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने और रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इस डील के तहत जापान की कंपनी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ऑस्ट्रेलिया की नौसेना रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी को कुल 11 आधुनिक युद्धपोत देगी। इनमें से 3 मोगामी-क्लास मल्टी-रोल फ्रिगेट 2029 से जापान में बनाए जाएंगे।

परिसीमन बिल गिरने के बाद केंद्र पर हमलावर हुए अभिषेक बनर्जी, महिला आरक्षण पर कही ये बात

कोलकाता, एजेंसी। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा में परिसीमन बिल के गिरने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस हार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बेचैनी को सबके सामने उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार को महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए।

शुक्रवार को लोकसभा में एक संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था। इस बिल का मुख्य उद्देश्य साल 2029 से विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करना था। साथ ही, इसमें लोकसभा सीटों की संख्या को बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव भी शामिल था। हालांकि, यह बिल सदन में गिर गया। वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि 230 सांसदों ने इसके विरोध में वोट दिया। सदन में मौजूद कुल 528 सदस्यों में से बिल को पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत यानी 352 वोटों की जरूरत थी, जिसे सरकार हासिल नहीं कर सकी।

अभिषेक बनर्जी का केंद्र पर हमला

अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि परिसीमन बिल की हार से भाजपा की घबराहट साफ दिख रही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन ने इस बिल को इसलिए खारिज किया क्योंकि इसमें निष्पक्षता और संतुलन को लेकर गंभीर चिंताएं थीं। सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 करने की कोशिश कर रही थी, जो सही नहीं था।

महिला आरक्षण के मुद्दे पर क्या बोले अभिषेक बनर्जी

टीएमसी सांसद ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि एनडीए सरकार अब बहुत कम समय के लिए बची है। उन्होंने कहा कि सत्ता पर सरकार की पकड़ अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ रही है। महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर बनर्जी ने जोर देकर कहा कि 33 प्रतिशत कोटा देने वाला कानून सितंबर 2023 में ही सर्वसम्मति से पास हो चुका है। यह कानून 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी भी है। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए सरकार वाकई गंभीर है, तो उसे तुरंत सीटों को अधिसूचित करने के लिए बिल लाना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि टीएमसी ने पहले ही संसद में महिलाओं को 41 प्रतिशत से ज्यादा प्रतिनिधित्व देकर मिसाल पेश की है। विपक्षी दलों का कहना है कि वे महिला आरक्षण का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसे विवादित परिसीमन प्रक्रिया से अलग रखा जाना चाहिए। इस बिल में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव था ताकि महिलाओं को आरक्षण दिया जा सके।

'दहेज देने की बात स्वीकार करने मात्र से पत्नी के परिवार पर नहीं चलेगा केस', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मामलों में स्पष्ट किया है कि यदि पत्नी अपनी शिकायत में लिखती है कि उसने दहेज दिया था, तो सिर्फ इस आधार पर उसके या उसके परिवार के खिलाफ दहेज देने का केस नहीं चलाया जा सकता है।

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने पति की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने दहेज अधिनियम की धारा 3 के तहत दहेज देने के अपराध के लिए पत्नी के परिवार के खिलाफ अलग से FIR दर्ज करने की मांग की थी। पति ने तर्क दिया कि पत्नी ने अपनी शिकायत में दहेज देने की बात स्वीकार की है, इसलिए यह अपराध बनता है। इस पर शीर्ष कोर्ट ने कहा कि धारा 7(3) पीड़ित को अभियोजन से बचा सकती है, ताकि वह बिना डर के शिकायत दर्ज करा सकें। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि दहेज देने के स्वतंत्र और ठोस सबूत हों, जो केवल शिकायत या बयानों से अलग हों, तब दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत कार्रवाई संभल है।

दहेज अधिनियम की धारा 3 में क्या प्रविधान?

मूल रूप से धारा 3 दहेज देने और लेने दोनों के समान रूप से दंडित करती थी। हालांकि, 1982 की संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। समिति ने पाया कि दहेज देने वाले अक्सर अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित होते हैं और सामाजिक मानदंडों से विवश होते हैं।

एक दिन का ट्रेलर आउट : साई पल्लवी और जुनैद खान की मैजिकल लव स्टोरी जगा रही प्यार की उम्मीद

आमिर खान प्रोडक्शंस की आने वाली फिल्म एक दिन, जिसमें साई पल्लवी और जुनैद खान लीड रोल में हैं, एक प्यारी और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी का वादा करती है। वाकई यह एक ऐसी फिल्म है जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अपने रूहानी गानों के साथ एक शानदार माहौल बनाने के बाद, अब मेकर्स ने इसका एक दिलचस्प ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जो उम्मीद और जादू से भरी एक प्रेम कहानी को बेहद खूबसूरती से पेश करता है।

एक दिन का ट्रेलर आखिरकार आ गया है, और यह एक जादुई प्रेम कहानी से रूबरू कराता है। जुनैद खान ने एक शर्मीले और थोड़े अलग लड़के का किरदार निभाया है, जिसे साई पल्लवी से प्यार हो जाता है, जो एक खुशमिजाज और जिंदादिल लड़की है। वैसे तो वे दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन जुनैद उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते।

हालांकि, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जापान में साई का एक्सीडेंट हो जाता है और वह ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेशिया की शिकार हो जाती है, जिसमें उसे सिर्फ जुनैद याद रहता है, जिसने उसकी जान बचाई थी। जहां यह मोड़ पूरी कहानी का रुख बदल देता है, वहीं यह देखना वाकई रोमांचक होगा कि यह प्रेम कहानी कैसे आगे बढ़ती है और क्या मोड़ लेती है।

ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही यह साफ हो गया है कि एक शालीन, कोमल और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी आने वाली है। यह कहानी प्यार में यकीन रखने, उम्मीद को थामे रहने और जादू के होने का इंतज़ार करने के बारे में है। निश्चित रूप से, यह एक दुर्लभ कहानी है जो लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है।

एक दिन के जरिए आमिर खान और फिल्म मेकर मंसूर खान एक लंबे अरसे के बाद फिर साथ आए हैं, जिससे हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा क्रिएटिव जोड़ियों में से एक फिर से जिंदा हो गई है। साथ मिलकर उन्होंने दर्शकों को कयामत से कयामत तक, जो जीता वही सिकंदर, अकेले हम अकेले तुम और जाने तू।।। या जाने ना जैसी यादगार फिल्में दी हैं। एक दिन के साथ यह जोड़ी एक बार फिर रोमांस जॉनर में लौट रही है, जिससे फैंस के बीच नया उत्साह पैदा हो गया है।। उनके फिर से साथ आने ने उत्सुकता बढ़ा दी है, और दर्शक उस जादू को पर्दे पर दोबारा देखने के लिए बेताब हैं।

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्म एक दिन में साई पल्लवी और जुनैद खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन सुनील पांडे ने किया है और इसे आमिर खान, मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

आदि साई कुमार ने की नई फिल्म सायराबानू का एलान, पहला पोस्टर भी आउट

अपनी ब्लॉकबस्टर फ़ल्मि शंभला के लिए मशहूर आदि साई कुमार ने अपने अगले प्रोजेक्ट सैराबानू की घोषणा की है, जिसे फनी कृष्णा सिरिकी डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फ़ल्मि को हास्य मूवीज़ के बैनर तले राजेश डांडा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि कृष्णकांत पारुचुरी इसके को-प्रोड्यूसर हैं।

फ़ल्मि के पोस्टर में एक जीवंत, सपनों जैसा रोमांटिक माहौल दिखाया गया है, जिसमें दिल के आकार का एक गुलाबी बादल और चारमीनार व विजाग बीच रोड जैसी मशहूर जगहों वाला एक शानदार नज़ारा नज़र आता है। फ़ल्मि की कहानी एक अनोखी हिंदू-मुस्लिम प्रेम कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें हास्य का पुट भी है और जिसकी पृष्ठभूमि राजमुंदरी और हैदराबाद है।

राम रेड्डी, म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर शेखर चंद्र और एडिटर के तौर पर छोटा के प्रसाद शामिल हैं। फ़ल्मि की रेगुलर शूटिंग जल्द ही शुरू होगी।

आदि साई कुमार के हालिया प्रोजेक्ट्स में शनमुखा और क्रेज़ी फ़ेलो शामिल हैं, जिनमें एक अभिनेता के तौर पर उनकी बहुमुखी प्रतिभा देखने को मिली है। फ़ल्मि के निर्देशक फणी कृष्णा सिरिकी ने इससे पहले क्रेज़ी फ़ेलो पर काम किया था, जो कि एक ज़बरदस्त मनोरंजक फ़ल्मि थी।

बांधवी श्रीधर, आदि साई कुमार के साथ फ़ल्मि में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर जुड़ गई हैं। फ़ल्मि की टेक्निकल टीम में सिनेमैटोग्राफ़र के तौर पर

तलाक के एक महीने बाद हंसिका मोटवानी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'अगर आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं तो...'

हंसिका मोटवानी ने अपने तलाक के एक महीने बाद इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया है कि मुश्किल दौर में उनका साथ किन लोगों ने दिया था?

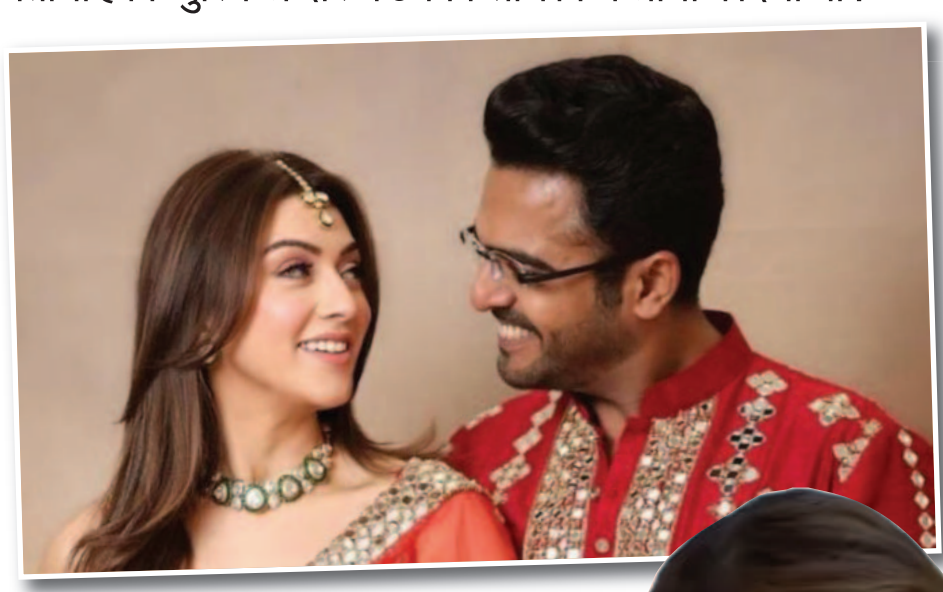

हाल ही में खबरें आईं कि अभिनेत्री हंसिका मोटवानी का सोहेल कथूरिया से तलाक हो गया है। लगभग एक महीने के बाद अभिनेत्री ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। 11 मार्च को मुंबई के बांद्रा में एक फैमिली कोर्ट ने दोनों की आपसी सहमति से तलाक दे दी। इस अलगाव ने लोगों का काफी ध्यान खींचा।

तलाक पर क्या बोलीं हंसिका?

हाउटरफ्लाई के साथ बातचीत में हंसिका ने कहा 'लोगों को सनसनी चाहिए थी, उन्हें मिल गई। उन्हें सुर्खियां चाहिए थीं, उन्हें मिल गईं। मैंने कभी इस पर सफाई नहीं दी, न ही दूंगी क्योंकि मेरे लिए यह कोई मायने नहीं रखता। यह ठीक है। मुझे कोई पछतावा नहीं है। अगर आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं, तो उसमें परेशान होने से बेहतर है कि आप उससे उतर जाएं।'

हंसिका का किसने दिया साथ?

उन्होंने आगे कहा कि वह अपने फैसले से संतुष्ट महसूस करती हैं और अब वह भावनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में हैं। हंसिका ने बताया कि उनके सबसे मुश्किल दौर में उनके परिवार ने उनका पूरी तरह से साथ दिया।

उन्होंने बताया कि उनकी मां और भाई ने बिना किसी शर्त उनका साथ दिया। उन्होंने हंसिका को एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरते देखा था, जो उनकी आमतौर पर खुशमिजाज स्वभाव को देखते हुए काफी चिंताजनक लग रहा था। सामने आई 'लव एंड वॉर' की रिलीज की तारीख, 'रामायण' के बाद सिनेमाघरों में दस्तक देगी रणबीर कपूर की फिल्म

अभिनेत्री निजी रखना चाहती हैं अपना फैसला

चीजों को निजी रखने के अपने फैसले को दोहराते हुए, उन्होंने कहा कि आखिर क्या गलत हुआ, इसकी जानकारी सिर्फ हम दोनों को ही है। उन्हें लगता है कि कुछ मामले सिर्फ उनसे जुड़े लोगों के बीच ही रहने चाहिए।

कब हुई हंसिका की शादी?

हंसिका और सोहेल खतूरिया ने दिसंबर 2022 में जयपुर के मुंडोता फोर्ट एंड पैलेस में एक भव्य समारोह में शादी की थी।

हंसिका का काम

काम की बात करें तो, हंसिका मोटवानी आखिरी बार 2024 की फिल्म 'गार्जियन' में नजर आई थीं। इस फिल्म में सुरेश चंद्र मेनन और श्रीमान ने भी अहम किरदार निभाए थे। जल्द ही वह तेलुगू फिल्म 'नशा' का हिस्सा होंगी।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com